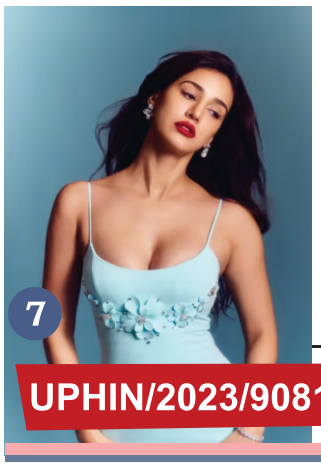
दी नेक्स्ट पोस्ट

साप्ताहिक



7

3 सीएम योगी ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं

5 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन

8 नायर ने पीले कपड़ों पर ली रोहित की चुटकी

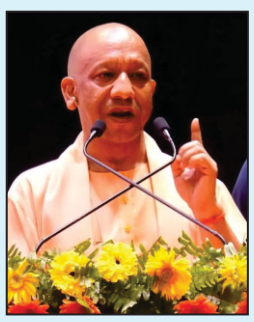
UPHIN/2023/90814 | वर्ष: 04, अंक: 13 | पृष्ठ संख्या: 8 | मूल्य: 1.00 रू. | सोमवार 21 सितम्बर, 2026

वे गिनते जाएं, हम नौकरियां देते जाएंगे

सीएम योगी ने किया 6 महीने में 1 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों का एलान



सीएम योगी ने दिया नियुक्ति पत्र



लोकभवन में 818 युवाओं को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र

अगले छह महीने में एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां मिलेंगी

पुलिस, होमगार्ड और शिक्षा क्षेत्र में भी होंगी बड़ी भर्तियां

साढ़े नौ लाख युवाओं को मिल चुकी सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अब तक प्रदेश के साढ़े नौ लाख युवाओं को पारदर्शी तरीके से विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दी गई है। नियुक्तियों का क्रम आगे भी जारी रहेगा। शनिवार को भी करीब एक हजार लोगों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगले छह महीने में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। जो लोग यह काम नहीं कर पाए, वे आज प्रश्न खड़े कर रहे हैं। वे गिनते जाएं, हम देते जाएंगे। एक लाख से कम युवाओं को नौकरी देने पर नहीं, उससे ज्यादा पर ही चर्चा होगी।

लखनऊ, संवाददाता

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जो लोग रोजगार नहीं दे पाए, वे आज सवाल खड़े कर रहे हैं। वे गिनते जाएं, हम नौकरियां देते जाएंगे। अगले छह महीने में एक लाख से कम नहीं, बल्कि एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रतिभाशाली युवा जब उत्तर प्रदेश की ताकत बनेंगे तो प्रदेश देश की नंबर वन अर्थव्यवस्था के रूप में खुद को स्थापित करेगा। मुख्यमंत्री योगी शुक्रवार को लोकभवन सभागार में मिशन रोजगार के तहत आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (न्च्ब्ब्) और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (न्च्ै) के माध्यम से आयुष, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम समेत विभिन्न विभागीय पदों पर चयनित 818 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी ने नवचयनित युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें उनके परिश्रम का प्रतिफल मिला है और अब वे उत्तर प्रदेश सरकार के अलग–अलग विभागों का हिस्सा बन रहे हैं।

पुलिस में 36 हजार, होमगार्ड में 41 से 42 हजार नियुक्तियां

मुख्यमंत्री योगी ने आगामी नियुक्तियों का ब्योरा देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 36 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं। उनकी परीक्षाएं पूरी हो चुकी हैं और फिजिकल व मेडिकल की प्रक्रिया चल रही है। होमगार्ड में भी 41 से 42 हजार नियुक्तियां हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से अगले छह महीने में आने वाले परिणामों के माध्यम से 25 से 30 हजार नए युवाओं को अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग से करीब 20 से 25 हजार नौजवानों को अवसर मिलने वाला है। कुछ के परिणाम आने शुरू हो गए हैं और कुछ की परीक्षाएं चल रही हैं। अगले तीन से चार महीने में इनके परिणाम भी सामने आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी अलग–अलग विभागों में 15 से 16 हजार युवाओं को अवसर मिलेगा।

भर्ती बोर्ड राजनीति का शिकार न हों तो ऐसे मिलते हैं परिणाम

मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती प्रक्रिया समयबद्ध, पारदर्शी और शुचितापूर्ण तरीके से पूरी करने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भर्ती बोर्ड और आयोग शासन की राजनीति का शिकार नहीं होते और परीक्षाएं पारदर्शी व शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न होती हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही देखने को मिलते हैं।

सीएम योगी ने 21 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र बोले– हमने ग्रुप–3 व 4 भर्ती में इंटरव्यू सिस्टम बंद किया

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगले छह महीनों में उत्तर प्रदेश के एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी, समयबद्ध और मेरिट आधारित बनाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने आयोगों और भर्ती बोर्डों को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होकर काम करने की आवश्यकता बताई। योगी सरकार की ओर से शनिवार को प्रदेश भर में 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया। उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग व उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के तहत व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग में अनुदेशक, सूक्ष्म–लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी, आयुष विभाग में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरर व फार्मासिस्ट तथा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर चयनित युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला। उन्होंने कहा कि हमने मॉडर्न व ट्रेडिशनल मेडिसिन पर काम किया। अब आयुष विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज आदि बन रहे हैं।

जब चीनी सेना ने हमें हिरासत में ले लिया था

आईआईटी रुड़की में एनएसए अजीत डोभाल ने सुनाया किस्सा

संवाददाता, रुड़की। एनएसए अजीत डोभाल ने आईआईटी रुड़की के दीक्षा समारोह में छात्रों से अपने शुरुआती करियर का एक किस्सा साझा किया। आईआईटी रुड़की के दीक्षा समारोह में एनएसए अजीत डोभाल ने छात्रों से कहा कि उनके बीच आकर वे दुविधा में हैं कि वह उनसे क्या विचार साझा करें। ऐसे में वह अपने जीवन के कुछ संस्मरण उनके साथ साझा करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को किन–किन खतरों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में सिक्किम में खुफिया मिशन पर काम करने के अनुभव साझा करते हुए कहा कि एक बार उनकी खुफिया टीम रास्ता भटक कर सीमा पार चली गई थी। चीनी सेना ने कुछ समय के लिए उन्हें हिरासत में ले लिया था। बाद में उन्हें सुरक्षित छोड़ दिया गया था। लेकिन उस वक्त उन्हें लगा कि उनका करियर खत्म हो गया है।



रंगों के फेर में फंसी सियासत

अम्बेडकरनगर,संवाददाता। चुनाव से पहले यूपी की सियासत रंगों के फेर में फंसती दिख रही है। मंत्री ओपी राजभर ने सपा के नीले साफे और भगवा रंग पर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। साथ ही राहुल गांधी पर भी जुबानी हमला बोला। यूपी के अंबेडकरनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री एवं सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शनिवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा।

उन्होंने अखिलेश यादव के नीले साफे पर तंज कसते हुए कहा कि इसे देखकर दलित समाज को सावधान हो जाना चाहिए। नीले रंग को 2 जून के स्टेट गेस्ट हाउस कांड, प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने और महापुरुषों के नाम पर रखे जिलों व अस्पतालों के नाम बदले जाने से भी जोड़ा। साथ ही सपा सरकार के फैसलों की आलोचना की।

जिले केप्रभारी मंत्री ने अखिलेश के भगवा रंग अपनाने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सपा के शासनकाल में रामभक्तों पर गोली चलाने की घटना की याद आती है, जबकि वर्तमान में भगवा रंग योगी आदित्यनाथ सरकार में माफिया और गैंगवार के खिलाफ कार्रवाई का प्रतीक बन गया है।

सपा पर सनातन विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने डिंपल यादव के पुराने बयान का भी उल्लेख।

प्रदेश में 13 पीसीएस अधिकारियों का तबादला

कई जिलों के एडीएम और नगर आयुक्त बदले

लखनऊ,संवाददाता। उत्तर प्रदेश शासन ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 अधिकारियों के तबादले किए। अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कुशीनगर, अयोध्या, कानपुर नगर, कासगंज, चित्रकूट, सहारनपुर, बरेली, मऊ और शाहजहांपुर समेत कई जिलों में अधिकारियों की तैनाती बदली गई। प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 अधिकारियों के तबादले किए हैं। तबादला सूची में अपर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, नगर आयुक्त समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। पवन कुमार, प्रधान प्रबंधक, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कुशीनगर बनाया गया है। दिनेश, मुख्य राजस्व अधिकारी, मऊ को अपर जिलाधिकारी (नगर), अयोध्या की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं सौरभ सिंह, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा को अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर बनाया गया है।

आलोक कुमार गुप्ता, अपर जिलाधिकारी (नगर), कानपुर नगर को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), कासगंज भेजा गया है। अरुण कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), चित्रकूट एवं उपसंचालक चकबंदी, चित्रकूट को संयुक्त निदेशक (प्रशासन), मत्स्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ बनाया गया है। कंचन, उप जिलाधिकारी, मथुरा को अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), चित्रकूट एवं उपसंचालक चकबंदी, चित्रकूट की जिम्मेदारी मिली है। सूरज कुमार यादव, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अपर नगर आयुक्त, नगर निगम सहारनपुर बनाया गया है।

इसी तरह जितेंद्र कटियार, उपजिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को उपनिदेशक (प्रशासन), आयुर्वेद निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ भेजा गया है। वंदिता श्रीवास्तव, सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण को उपनिदेशक (प्रशासन), उच्च शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज बनाया गया है।

ट्रंप का ड्रीम प्रोजेक्ट गोल्डन डोम

दुर्लभ धातुओं के खजाने पर रूस–चीन की नजर ग्रीनलैंड समझौते से कैसे बिगड़ा गणित



अमेरिका–ग्रीनलैंड इन्फिनाइट लाइफ समझौता केवल द्वीप की सुरक्षा नहीं, बल्कि रूस–चीन को रोकने के साथ–साथ दुर्लभ खनिजों और मिसाइल रक्षा प्रणाली पर दबदबा बनाने का मास्टरस्ट्रोक भी है।

वॉशिंगटन,एजेंसी। वैश्विक कूटनीति के पटल पर एक बार फिर आर्कटिक महासागर के ठंडे पानी में गर्माहट आ गई है। वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने डेनमार्क और ग्रीनलैंड के साथ एक ऐतिहासिक इन्फिनाइट लाइफश समझौते का एलान किया है। इस डील के तहत अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर श्स्थायी नियंत्रणश मिल गया है। बड़ी बात यह है कि इस समझौते से केवल ट्रंप को ग्रीनलैंड की सुरक्षा पर स्थाई नियंत्रण ही नहीं मिला है, बल्कि चीन और रूस की घेराबंदी के लिए मास्टरस्ट्रोक माने जाने वाला यह समझौता अंतरराष्ट्रीय समीकरणों को पूरी तरह से बदलने की ताकत भी रखता है।

केवल एक द्वीप की सुरक्षा तक नहीं सीमित है यह समझौता...

अब इस बात में तो कोई दोहराई नहीं है कि देखने और सुनने में भले ही यह एक आम रक्षा समझौते की तरह लगे, लेकिन इसके सामरिक मायने बेहद गहरे हैं। इस बात को ऐसे समझिए कि यह डील महज एक द्वीप की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भविष्य के महायुद्धों, मिसाइल डिफेंस सिस्टम और वैश्विक खनिज बाजार पर वर्चस्व की एक बड़ी लड़ाई का हिस्सा भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस एक समझौते से वैश्विक कूटनीति की पटल से लेकर महायुद्धों तक कैसे प्रभावित हो सकते हैं? दूसरी बड़ी बात आखिर ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ अमेरिका के इस समझौते से रूस और चीन चिंता में क्यों है? इतिहास क्या कहता है, भूगोल का तर्क क्या है।

सम्पादकीय

नशे का नया संप्रदाय

पर्यटन का कचरा या कचरे में पर्यटन का एक महीन रिश्ता धर्मशाला के धर्मकोट में नजर आया। हालांकि पुलिस ने रेव पार्टी का सामान चुराते हुए सारा कचरा उठा दिया, लेकिन बार–बार यह नौबत क्यों और कैसे आ रही। पर्यटन जब कंद्राओं में मनोरंजन ढूंढता है, तो यह कचरे का व्यापार हो सकता है। पर्यटन के मार्फत शिकार या शिकारियों के जाल में पर्यटन की परिभाषा दूषित हो रही है और यही गाहे बगाहे मनाली और धर्मकोट की बाहों में पनप जाता है। बेशक धर्मकोट में दो बार रेव पार्टियों को तहस नहस करके पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी है, लेकिन पर्यटन में तेजी से फैल रहा नशे का संप्रदाय नित नए प्रयोग करने लगा है। कचरा सिर्फ नशे का नहीं जिस्मफरोशी का भी है। पर्यटन की कई परतें और कई विषाद हैं और जब गंतव्य सामान्य गतिविधियों के अखाड़े बन जाते हैं, तो कई काले अध्याय भी साथ निकल आते हैं। तथाकथित रेव पार्टियों के सामान को ढोती तरह–तरह की अनुमतियां भी कलंकित हो रही हैं। हालिया अदालती हस्तक्षेप से कुल्लू के दो अधिकारियों को बदलना पड़ा था।

यह पर्यटन विभाग की चौकसी व दुरुस्ती का सवाल भी है। होटल इंस्पेक्टर जैसे पदों की परिभाषा में वातावरण की शुद्धि निहित है, लेकिन ऐसी व्यवस्था बनी ही नहीं। दूसरे टीसीपी कानून के तहत हर तरह के पर्यटन परिसर की व्याख्या व अनुमति का ठोस आधार होना चाहिए। नई मंजिलों की तलाश में नित नए पर्यटन परिसर मानव बस्तियों से दूर एकांत में व्यवस्था से दूर अपनी संदिग्ध व्यवस्था बना रहे हैं, तो पर्यटन इकाइयों के उद्देश्य व उनके ग्राहकों की समीक्षा जरूरी है। यह केवल डेस्टिनेशन पर ही खतरा नहीं, बल्कि हाई वे टूरिज्म पर भी नीति–निर्देश तथा चौकसी चाहिए। हम पर्यटन को प्रदेश के प्रवेश द्वारों पर चिन्हित नहीं करते, लिहाजा भीड़ और सैलानियों के बीच खरे और खोटे का अंतर समाप्त हो जाता। गलत कारणों से कसोल व धर्मकोट का प्रचार सही मायनों में पर्यटकों की कैटेगिरी पैदा नहीं करता। चुनौती सही यात्री, हाई एंड टूरिस्ट या सोलो ट्रैवलर से नहीं, बल्कि पर्यटन से जुड़े अपराधियों से है। पर्यटन के व्यापार ने कुछ आपराधिक नेटवर्क अपने साथ जोड़ लिया है। इसका अपना एक राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है। गोवा हो या राजस्थान, कुछ पर्यटन आपरेटर ऐसी शैली विकसित करते हैं, जो आपराधिक चरित्र की मौज मस्ती तक ही सीमित रहती। जाहिर है हिमाचल में गिने जा रहे समस्त बाहरी लोग पर्यटक नहीं हैं और न ही उनके कारण पर्यटन में गुणवत्ता आ रही है। चंद पैसों के लिए नशा अगर इसका आकर्षण बन जाए, तो हिमाचल अपने वांछित सपने पूरा नहीं कर पाएगा। यानी पर्यटन में माफिया की शिरकत रोकने के लिए पूर्ण बंदोबस्त चाहिए। बहरहाल नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान सक्रियता के साथ मामले पकड़ रहा है, लेकिन पर्यटन के रास्ते अपराध प्रवेश न करे, इसके लिए चौकसी की नई व्यवस्था प्रवेश द्वारों से चाहिए। पर्यटकों का पंजीकरण हिमाचल के प्रवेश द्वारों पर ही होना चाहिए और यह ऐप द्वारा संचालित हो तो सारी जानकारियों में स्पष्टता आएगी। पर्यटन के रास्ते आ रही संवेदनहीनता को समझते हुए तमाम आपरेटरों खास तौर पर लीज पर चल रहे होटलों, होस्टलों तथा ऐसी विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण–परीक्षण की पूर्ण व्यवस्था स्थायी रूप से बनानी पड़ेगी।

अमेरिका की मनमानी

आखिरकार अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने भी रूस से तेल आयात करने वाले भारत समेत पांच प्रमुख देशों पर सौ प्रतिशत टैरिफ लगाने वाले बिल को स्वीकृति दे दी। इससे पहले सीनेट भी इस विधेयक को मंजूरी दे चुकी है। यदि अमेरिकी राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो भारत, चीन के अतिरिक्त हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान पर अमेरिकी टैरिफ और अधिक बढ़ जाएगा। देखना है कि यह सौ प्रतिशत होता है या उससे कम? देखना यह भी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति इस विधेयक पर हस्ताक्षर करते हैं अथवा उसे रूस से तेल खरीदने वाले देशों को केवल दबाव में लेने का जरिया बनाना चाहते हैं। जो भी हो, यदि अमेरिका भारत पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाता है तो अपने अहंकार का ही परिचय देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति और उक्त विधेयक का समर्थन करने वाले पक्ष–विपक्ष के सांसदों का यह मानना है कि रूस से तेल खरीदने वाले देशों को टैरिफ के जरिये दंडित करने से वह यूक्रेन के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखने में असमर्थ हो जाएगा।

यह सही है कि रूस यूक्रेन के खिलाफ एक अंतहीन और एक तरह से निरर्थक लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन यह कहना समस्या का सरलीकरण ही है कि यह युद्ध भारत, चीन जैसे देशों के कारण जारी है। क्या यह विचित्र नहीं कि अमेरिका अपने ही द्वारा ईरान के खिलाफ छेड़े गए युद्ध को तो रोक नहीं पा रहा है और भारत, चीन आदि पर इसका दोष मढ़ रहा है कि वे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में रूस की सहायता कर रहे हैं? यह अच्छा हुआ कि भारत ने अमेरिका की मनमानी का परिचय देने वाले विधेयक पर दो टूक कहा कि वह अपने ऊर्जा हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए हरसंभव उपाय करेगा। इसका संकेत यही है कि यदि अमेरिका रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर सचमुच टैरिफ बढ़ाता है तो उसे इसका जवाब भी दिया जाएगा। यह संभव नहीं कि अमेरिका मनमानी करता रहे और भारत चुपचाप उसे सहता रहे। यदि अमेरिका ने अपना रवैया नहीं बदला तो भारत के साथ उसके संबंध और अधिक बिगड़ने तय हैं।

यह भी संभव है कि अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार समझौता अंतिम रूप न ले सके। अमेरिका को यह समझना होगा कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यदि वह भारत से संबंध सुधारना चाहता है तो उसे मित्रवत व्यवहार करना होगा। उसे इसका भी आभास होना चाहिए कि यदि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो एक तो उसके ऊर्जा हित खतरे में पड़ जाएंगे और दूसरे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम और अधिक बढ़ जाएंगे। ध्यान रहे पश्चिम एशिया संकट के कारण ये पहले से ही बढ़े हुए हैं और यह संकट अमेरिका ने ही खड़ा किया है।

यूपीआई 'मुफ्त' नहीं

प्रधानमंत्री मोदी जो ढिंढोरा पीट रहे थे और देश की जनता को आश्वस्त कर रहे थे, उसका ढोल फट चुका है और सच सामने है। सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के जरिए ऐलान कराया है कि अब डिजिटल भुगतान (यूपीआई) 'मुफ्त' नहीं होगा, बल्कि प्रत्यक्ष–परोक्ष रूप से आम ग्राहक, आम उपभोक्ता, आम आदमी की जेब कटेगी। अब यह यथार्थ भी सामने आ सकता है कि नकदी लेन–देन की ओर वापसी होने लगे! आम आदमी को यूपीआई लेन–देन की लत लग चुकी थी। उसे यह व्यवस्था आसान और सहज लगती थी। वह औसतन हर भुगतान यूपीआई के जरिए ही करने लगा था। फुटपाथ के पास रेहड़ी–पटरी, चायवाला अथवा टोकरी में फल बेचने वाली निरक्षर–सी महिला 'स्कैन' के जरिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करने लगे थे। इसकी लोकप्रियता, व्यापकता का पुख्ता प्रमाण यही है कि यूपीआई से साल भर में 314.23 लाख करोड़ रुपए का लेन–देन किया गया। यूपीआई इस्तेमाल करने वालों की संख्या 24,162 करोड़ बताई गई है। यूपीआई के जरिए रोजाना औसतन 66 करोड़ बार लेन–देन होता है। करीब 67 फीसदी भुगतान 2000 रुपए से अधिक का किया गया, बेशक सरकार ऐसा करने वालों की संख्या मात्र 4 फीसदी और 2000 रुपए से कम वाले 96 फीसदी बता रही है। दरअसल इन 4 फीसदी का मूल्य ही 67 फीसदी है। बेशक भारत सरकार की अधिसूचना में उल्लेख है कि व्यक्ति से व्यक्ति अथवा 2000 रुपए तक का लेन–देन करने वालों पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क वैसे भी दुकानदार, व्यापारी, यानी मर्चेन्ट को भरना होगा, लिहाजा इस शुल्क को 'एमडीआर' का नाम दिया गया है। यह बड़ी हास्यास्पद और बेवकूफ बनाने वाली व्यवस्था है।

किराने, दूध–दही का दुकानदार या दवाओं की दुकान अथवा टीवी, फ्रिज, मोबाइल के शोरूम, अंततरू, यह 'हर्जाना' क्यों भुगतेंगे? बैंक कितनी निगरानी रख सकते हैं? वे किसी को भुगतान की प्रणाली के लिए बाध्य नहीं कर सकते। एनपीसीआई ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 0.4 फीसदी और 75,000 रुपए या अधिक के बड़े लेन–देन के लिए अधिकतम शुल्क 300 रुपए तय किया है। आपको अब रेलवे, टेलीकॉम, बीमा, पेट्रोल पंप पर ईंधन लेने और कृषि इनपुट सरीखे जरूरी भुगतान पर 5 रुपए (प्रति लेन–देन) शुल्क देना होगा। स्कूल–कॉलेज की फीस 2000 रुपए से अधिक की है, तो उस पर 300 रुपए की फ्लैट दर देनी होगी। आम आदमी पर बोझ कैसे नहीं पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी? संभव है कि डिजिटल भुगतान के मद्देनजर जितने लाखों करोड़ रुपए का लेन–देन हो रहा है, उससे टैक्स वसूलने का लालच सरकार ने महसूस किया होगा! यह सवाल भी सामने होगा कि यूपीआई के व्यापक, विविध नेटवर्क पर 20,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च क्यों किए जाएं?

समय की मांग है यूपीआई को सक्षम बनाना

वित्त वर्ष 2025–26 में यूपीआई से 24,162 करोड़ लेनदेन हुए। यानी रोज औसतन 66 करोड़ से अधिक भुगतान। इसकी सेवाएं अब 11 अन्य देशों तक पहुंच चुकी हैं। भारत में बनी यह व्यवस्था हमारी रोजमर्रा की जरूरत बन गई है। अब चुनौती है कि नागरिकों को यह सुविधा मुफ्त मिलती रहे और इसे सुरक्षित एवं भरोसेमंद बनाए रखने के लिए पर्याप्त धन भी उपलब्ध हो। यूपीआई पर सेवा शुल्क की बहस को इसी नजरिये से समझना चाहिए। इस क्रम में सबसे पहले आम लोगों की चिंता दूर करना जरूरी है। नई व्यवस्था में बैंक खाते से होने वाला सामान्य यूपीआई भुगतान ग्राहकों के लिए मुफ्त रहेगा। परिवार या मित्रों को पैसे भेजने पर न भेजने वाले से शुल्क लिया जाएगा और न ही पाने वाले से। मुफ्त उपयोग का कोई मासिक कोटा नहीं है। अधिक रकम भेजने या बार–बार भुगतान करने से शुल्क नहीं लगेगा। सुरक्षा के लिए तय लेनदेन सीमाएं अपनी जगह हैं। दो हजार रुपये की सीमा कुछ दुकानदारों से लिए जाने वाले शुल्क से जुड़ी है। नागरिकों के लिए मुफ्त सुविधा पर कोई सीमा नहीं है।

इसे मीरा की खरीदारी से समझिए। वह एक बड़े दुकानदार से 10,000 रुपये का फ्रिज खरीदती है। दोनों के खाते भारतीय बैंकों में हैं। मीरा का एप भुगतान का निर्देश भेजता है। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया यानी एनपीसीआई इसे बैंकों के बीच पहुंचाता है। एक बैंक मीरा के खाते से पैसे काटता है और दूसरा दुकानदार के खाते में जमा करता है। एप इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था की मदद से भुगतान कराता है। डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले दुकानदार जो सेवा शुल्क देता है, उसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर कहते हैं। यदि मीरा का दुकानदार छूट वाली श्रेणी में नहीं आता, तो 15 अक्टूबर 2026 से इस खरीद पर 0.4 प्रतिशत अर्थात 40 रुपये एमडीआर लगेगा। मीरा के लिए फ्रिज की कीमत 10,000 रुपये ही रहेगी। दुकानदार उसके बिल में एमडीआर नहीं जोड़ सकता और एप भी छिपा हुआ शुल्क नहीं वसूल सकता।

इसी श्रेणी में एक लाख रुपये की खरीद पर एमडीआर अधिकतम 300 रुपये होगा। मीरा अपनी मां को 10,000 रुपये भेजे, तो दोनों के लिए शुल्क शून्य रहेगा। मीरा की खरीद में दुकानदार के 40 रुपये एमडीआर पर 18 प्रतिशत जीएसटी यानी 7.20 रुपये जुड़ेगा। कुल खर्च 47.20 रुपये होगा। पात्र दुकानदार को चुकाए गए इस कर का समायोजन यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल सकता है। पूरे 10,000 रुपये के भुगतान पर अलग से 18 प्रतिशत कर नहीं लग रहा। मीरा का यूपीआई लेनदेन शुल्क शून्य ही रहेगा। सवाल है कि यूपीआई पर शुल्क क्यों लगाया गया? शुरुआत में प्राथमिकता लोगों को यूपीआई से जोड़ना थी। सरकारी सहायता ने इसमें मदद की। अब हजारों करोड़ लेनदेन संभालने के लिए ज्यादा क्षमता वाले सर्वर, साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और ग्राहक सहायता पर खर्च बढ़ा है। इन जरूरतों पर लगभग 20,000 करोड़ रुपये सालाना खर्च होते हैं। इसे जांच–परख कर तय किया गया घाटा समझना गलत होगा। नकदी संभालने का खर्च घटने से होने वाली बचत और दूसरी संबंधित आय भी हिसाब में शामिल होनी चाहिए। फिर भी, बैंकों का मुनाफा या सरकारी सहायता इस संचालन खर्च को समाप्त नहीं करती।

इस बहस का राजनीतिक पक्ष भी है। वित्तीय मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने 12 अगस्त को लेनदेन की अलग–अलग श्रेणियों के अनुसार शुल्क से आय जुटाने का समर्थन करने वाली रिपोर्ट स्वीकार की। इनमें कांग्रेस के पांच सांसद भी थे। किसी ने आपत्ति नहीं की। समिति में यूपीआई के लिए नियमित आय का समर्थन करना और बाहर उसे नागरिकों पर बोझ बताना विरोधाभासी है। अमेरिकी दबाव का आरोप भी प्रमाण मांगता है। रिजर्व बैंक ने 17 अगस्त 2022 को ही यूपीआई की लागत वसूली पर चर्चा के लिए दस्तावेज जारी किया था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की 2026 की रिपोर्ट भारत की उस प्रस्तावित सीमा पर आपत्ति करती है, जिसके तहत किसी एक गैर–बैंक भुगतान एप की हिस्सेदारी यूपीआई के कुल लेनदेन की संख्या में 30 प्रतिशत से अधिक न हो। यह एप की बाजार हिस्सेदारी की सीमा है, ग्राहकों के भुगतान की नहीं। रिपोर्ट यूपीआई के जरिये उधार आधारित भुगतान पर पाबंदियों का भी विरोध करती है। उसमें भारत द्वारा 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का कोई वादा दर्ज नहीं है। अमेरिकी आपत्ति से यह साबित नहीं होता कि भारतीय फैसला उसके ही दबाव में हुआ। इसी रिपोर्ट के अनुसार, 2025 के अंत में अमेरिकी स्वामित्व वाले दो एप से 80 प्रतिशत से अधिक यूपीआई लेनदेन हो रहे थे। उनका दबदबा शून्य एमडीआर के दौर में बना। किसी एप से ज्यादा भुगतान होने का अर्थ यह नहीं कि शुल्क का सबसे बड़ा हिस्सा भी उसे मिलेगा। उद्योग के शुरुआती अनुमानों में एमडीआर का करीब 60 प्रतिशत बैंकों, 25 प्रतिशत एप कंपनियों और 15 प्रतिशत दुकानदारों को भुगतान स्वीकार करने की सुविधा देने वाली कंपनियों को मिलता है। मीरा का उपरोक्त ही उदाहरण लें तो उनकी खरीद के 40 रुपये में बैंकों को 24, एप कंपनियों को 10 और अन्य संबंधित कंपनियों को छह रुपये मिलेंगे। यहां ग्राहक और दुकानदार, दोनों के बैंक भारतीय हैं। सबसे बड़ा हिस्सा उन्हीं का होगा। वे भुगतान की जांच, खातों में रकम पहुँचाने और शिकायतें सुलझाने का काम करते हैं। ये हिस्सेदारियां अनुमान हैं, लेकिन अधिकांश शुल्क अमेरिकी एप को मिलने वाले दावे का समर्थन नहीं करतीं। यूपीआई का संचालन भी भारतीय नियामकीय निगरानी में एनपीसीआई ही करता है।

दुकानदार यूपीआई की सफलता के साझेदार हैं। उनकी सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है। छूट और रियायती दरों के साथ छोटे दुकानदारों के लिए बनने वाला कोष भी मददगार होगा, जिसमें कुल एमडीआर वसूली के पांच प्रतिशत के बराबर राशि दी जाएगी। शुल्क का बंटवारा स्पष्ट हो और समय–समय पर समीक्षा से व्यावहारिक दिक्कतें दूर की जाएं। नागरिकों को मुफ्त भुगतान, छोटे दुकानदारों को संरक्षण और पूरे तंत्र को सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन मिलते रहें। इसी से यूपीआई पर लोगों का भरोसा आगे भी मजबूत रहेगा।

सीएम योगी ने सुनीं 150 लोगों की समस्याएं

गोरखपुर में जनता दर्शन





गोरखपुर,संवाददाता। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान गुरुवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे लोगों से उन्होंने कहा कि सरकार इलाज में पूरी मदद करेगी। इसके लिए जरूरतमंद लोगों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जाएगा और इसके बाद भी जरूरत पड़ी तो विवेकाधीन कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर जरूरतमंद, पात्र व्यक्ति का आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें इलाज के लिए परेशान न होना पड़े।

महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। उनके पास जाकर उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्रों का अवलोकन कर समस्या, शिकायत का संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि वे परेशान न हों, सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। उन्होंने अलग–अलग मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित और हस्तगत किए। साथ ही निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिप्रद होना चाहिए।

दिव्यांग के इलाज की व्यवस्था, पेंशन भी बहाल होगी

जनता दर्शन में देवरिया जनपद से आए एक दिव्यांग ने इलाज के लिए सहायता देने का निवेदन किया। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को समुचित व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया। दिव्यांग से बातचीत में जैसे ही सीएम को उसका आयुष्मान कार्ड न होने की जानकारी हुई तो उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जल्द से जल्द आयुष्मान कार्ड बनवा दिया जाए। सीएम ने उससे दिव्यांग पेंशन के बारे में भी पूछा तो पता चला कि पेंशन मिलती थी, लेकिन किंचित कारणों से अभी बंद है। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उक्त दिव्यांग की पेंशन बहाल कराने के लिए निर्देशित किया।

गोशाला में गोसेवा की सीएम ने गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही। प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ और अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गोशाला में गोसेवा की। गोवंश को अपने हाथ से गुड़ खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया। उन्होंने गोशाला के कार्यकर्ताओं से गोवंश के स्वास्थ्य एवं टीकाकरण की जानकारी ली और देखभाल के जरूरी दिशानिर्देश दिए।

ब्रिटिश नागरिक जार्डन गोरखपुर से तिहाड़ जेल शिफ्ट

गोरखपुर,संवाददाता। नेपाल सीमा पर सोनौली से पकड़े गए ब्रिटिश नागरिक जॉर्डन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट ने उसे 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है। 11 जुलाई 2026 को इंडो नेपाल के सोनौली से गिरफ्तार किया गया जार्डन अक्टूबर 2025 में दिल्ली एयरपोर्ट से फरार अपराधी है। नेपाल सीमा पर सोनौली से पकड़े गए ब्रिटिश नागरिक जॉर्डन को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल भेज दिया है। कोर्ट ने उसे 29 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा है।जानकारी के अनुसार 11 जुलाई को जॉर्डन बिना वीजा–पासपोर्ट के नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान एसएसबी 22वीं वाहिनी ने उसे सीमा पर दबोच लिया था। उसके खिलाफ सोनौली कोतवाली में मुकदमा दर्ज है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज की कोर्ट में सुनवाई चल रही है।

अगली सुनवाई 28 सितंबर को मुकेश यादव की कोर्ट में सुनवाई लगी है। गिरफ्तारी के बाद उसे महराजगंज जिला कारागार में रखा गया था, जहां उपद्रव के चलते 29 जुलाई को उसे गोरखपुर जिला कारागार शिफ्ट कर दिया गया था।

गोरखपुर जेल में रहने के दौरान दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट थाने से उसे पेश करने का आदेश आया।

इस थाने में उसके खिलाफ थाईलैंड से डिपोर्ट होने के दौरान फरार होने का मुकदमा दर्ज है, जिसमें दिल्ली की स्पेशल टीम उसकी तलाश में फेल हो चुकी थी।

13 सितंबर को कोर्ट को पत्र देकर गोरखपुर कारागार प्रशासन उसे दिल्ली लेकर गया था। 16 सितंबर को आईजीआई एयरपोर्ट थाना पुलिस ने उसे पटियाला कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे तिहाड़ भेज दिया गया।

पहले उपेक्षा, अब सम्मान–सीएम योगी बोले–सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा

गोरखपुर,संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो देश शिल्पकारों व कारीगरों को सम्मान देता है, वही आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्लेटफॉर्म देकर शिल्प को आधुनिक तकनीक और नए बाजार से जोड़ा है। भगवान विश्वकर्मा की पावन जयंती पर शिल्पकारों–कारीगरों सहित समस्त प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो देश शिल्पकारों व कारीगरों को सम्मान देता है, वही आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसी भावना को अपनाकर पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्लेटफार्म दिया है। उन्होंने शिल्प व कारीगरी को आधुनिक तकनीक और नए बाजार से जोड़कर शिल्पकारों–कारीगरों को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाया है। सीएम योगी गुरुवार सुबह जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में आयोजित श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की विधि विधान से आराधना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमिस्त्री, बढ़ई, हलवाई, सोनार का काम करने वालों सहित कारीगरी के तमाम पेशे से जुड़े लोगों के लिए उनकी शिल्प कला ही स्वावलंबन का आधार थी। पर, यह



हुनर, शिल्प–कारीगरी आजादी के बाद दशकों तक उपेक्षा का शिकार रही।

पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन में पहली बार डबल इंजन सरकार ने शिल्पकारों–कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट और रोजगार के विभिन्न आयामों के साथ जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया है। डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन से यूपी में आज तीन करोड़ से अधिक लोग कारीगरी, शिल्प से जुड़कर रोजगार और स्वावलंबन की राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं। सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन अत्यंत पवित्र है। आज सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती है तो साथ ही आज नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। आज हर कारीगर, शिल्पी जिसके पास कोई विशिष्ट शिल्प है, वह पूजन के जरिये सृष्टि के शिल्पी प्रभु विश्वकर्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के सुदीर्घ स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए कहा, 'गुरु गोरखनाथ की पावन धरा से भगवान विश्वकर्मा के मंदिर में सृष्टि के शिल्पी के श्रीचरणों में नमन करते हुए मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की तरफ से हृदय से बधाई देता हूं। यह प्रार्थना है कि लंबे समय तक उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे और उनकी विकसित भारत की परिकल्पना साकार हो।' कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री विश्वकर्मा पूजनोत्सव पुस्तक का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री का स्वागत श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर समिति के अध्यक्ष दयानंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, स्थानीय पार्षद छट्ठीलाल गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, श्री विश्वकर्मा पंचायत मंदिर समिति से जुड़े जयप्रकाश शर्मा, अनूप शर्मा, अजय विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता रही।

यूपी एटीएस की कार्रवाई

गांव से रोजगार के लिए निकला था युवक कोयंबटूर से गिरफ्तारी हुई गिरफ्तारी

सिद्धार्थनगर,संवाददाता। मधवापुर गांव के 19 वर्षीय मकसूद अली की गिरफ्तारी से गांव में सन्नाटा है। रोजगार के लिए ढाई माह पहले निकला युवक पहले सूरत फिर कोयंबटूर में फर्नीचर कारीगर के सहायक के तौर पर काम कर रहा था। थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव का 19 वर्षीय मकसूद अली अब एटीएस की जांच का अहम नाम बन गया है। रोजगार की तलाश में करीब ढाई माह पहले घर से निकला युवक पहले सूरत और फिर तमिलनाडु के कोयंबटूर पहुंचा था, जहां वह फर्नीचर कारीगर के सहायक के रूप में काम कर रहा था। 14 सितंबर को यूपी एटीएस ने तमिलनाडु एटीएस की मदद से उसे कोयंबटूर से गिरफ्तार किया।

गांव में दिनभर इसी घटना की चर्चा रही। ग्रामीणों के मुताबिक मकसूद कक्षा नौ तक पढ़ा था और आर्थिक तंगी के कारण बाहर काम करने गया था। उसके पिता भुअर बीमारी और कमर की समस्या से परेशान हैं, इसलिए परिवार को उम्मीद थी कि बेटा कमाकर घर का सहारा बनेगा। मधवापुर के लोगों का कहना है कि उन्हें केवल इतना पता था कि मकसूद तमिलनाडु में फर्नीचर का काम करता है। उसके कथित ऑनलाइन संपर्कों या सोशल मीडिया गतिविधियों की जानकारी किसी को नहीं थी। गिरफ्तारी के बाद परिवार और ग्रामीण दोनों हैरान हैं।

नालियों की गंदगी से मिलेगी राहत- एआई करेगा प्लास्टिक की पहचान

गोरखपुर। नालियों में बहते प्लास्टिक कचरे को अब एआई पहचानकर रोबोटिक आर्म से बाहर निकलवाएगा। गोरखपुर और दिल्ली के शोधकर्ताओं ने यह तकनीक विकसित की है, जिसने परीक्षण में 97.4 प्रतिशत सटीकता हासिल की। जानिए, कैसे काम करेगा यह सिस्टम और क्या हैं इसकी खूबियां।

नालियों के पानी में बहते प्लास्टिक कचरे की पहचान अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) करेगी और उसे निकालने का काम रोबोटिक आर्म करेगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) और दिल्ली टेक्निकल विश्वविद्यालय के चार शोधकर्ताओं ने ऐसा एआई आधारित सिस्टम विकसित किया है। परीक्षण में सिस्टम ने प्लास्टिक कचरे की पहचान में 97.4 प्रतिशत सटीकता हासिल की है। इसे भारत सरकार की ओर से पेटेंट भी दिया गया है।

जेटसन एज डिवाइस और वास्तविक नाली के पानी में भी इसकी पहचान क्षमता का परीक्षण सफल रहा। सिस्टम विकसित करने वाली टीम में डॉ. अभिषेक वर्मा, दिनेश कुमार विश्वकर्मा, सुमित कुमार और प्रतीक सैनी शामिल हैं। डॉ. अभिषेक वर्मा कंप्यूटर साइंस विभाग में सहायक आचार्य हैं।

अन्य तीनों शोधकर्ता दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं। डॉ. अभिषेक के मुताबिक, इस तकनीक को 20 साल के लिए पेटेंट मिला है। अनुदान मिलने के बाद इसका पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर और सीएनएन आधारित कंप्यूटर विजन मॉडल, कैमरा और रोबोटिक आर्म को एकीकृत कर यह सिस्टम तैयार किया गया है। इसका इस्तेमाल नगर निगम की नालियों में पानी की सतह पर बहते प्लास्टिक कचरे को चुनकर बाहर निकालने में किया जा सकेगा। सिस्टम कचरे की तस्वीर या वीडियो लेकर पहले प्लास्टिक की पहचान करेगा।

4,000 से अधिक वास्तविक तस्वीरों से प्रशिक्षित

सिस्टम को 1,000 से अधिक शहरी और ग्रामीण स्थानों से जुटाई गई 4,000 से अधिक वास्तविक प्लास्टिक की तस्वीरों से प्रशिक्षित किया गया है। विशेषज्ञों ने तस्वीरों का सत्यापन किया। एआई प्लास्टिक की बनावट, चमक, आकार और ज्यामिति के आधार पर उसे पत्ते और लकड़ी जैसे जैविक कचरे से अलग करता है। कम रोशनी में काम करने के लिए आईआर या नाइट विजन कैमरे का इस्तेमाल किया जा सकता है।

एक घंटे में 600 से 900 टुकड़े उठाने की क्षमता

डॉ. अभिषेक के मुताबिक, सिस्टम एक घंटे में करीब 600 से 900 प्लास्टिक के टुकड़े उठा सकता है। वास्तविक क्षमता नाली के आकार और रोबोटिक आर्म पर निर्भर करेगी।

सामान्य स्थिति में एक बार में 500 ग्राम से दो किलोग्राम तक भार उठाया जा सकेगा। मॉड्यूलर फ्रेम के जरिये इसे नालियों पर लगाया जा सकता है। सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होगी। आईओटी डैशबोर्ड बिन भरने या सिस्टम में खराबी आने पर अलर्ट देगा।

गोरखपुर में पिछड़ी जातियों का बड़ा गणित आरक्षित सीटों पर बनी हुई है निगाह

पूर्वांचल में विधानसभा चुनावों से पहले पिछड़ों की राजनीति तेज हो गई है, जहाँ एनडीए और विपक्ष दोनों ही ओबीसी ...



पूर्वांचल में विधानसभा चुनावों से पहले ओबीसी राजनीति महत्वपूर्ण बनी
एनडीए और विपक्ष दोनों ओबीसी वोटों पर ध्यान केंद्रित कर रहे
भाजपा को सहयोगी दलों और विपक्ष दोनों से चुनौती मिल रही

गोरखपुर,संवाददाता। पूर्वांचल में पिछड़ों की राजनीति महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश जैसे–जैसे विधानसभा चुनावों की तरफ बढ़ रहा है वैसे–वैसे पूर्वांचल में आरक्षण की मांग से लेकर अलग पहचान की राजनीति का रंग गहरा होता जा रहा है। एनडीए हो या विपक्ष, गोरखपुर क्षेत्र की 62 विधानसभा सीटों पर सभी ओबीसी राजनीति के जरिये लखनऊ का मार्ग खोजना चाहते हैं। एनडीए के भीतर ही संजय निषाद और ओमप्रकाश राजभर अपने मुद्दे उठा रहे हैं। निषाद पार्टी आरक्षण के सहारे राजनीतिक वजन बढ़ाना चाहती है। वहीं, अपना दल (एस) कुर्मी हिस्सेदारी के आधार पर सीटों में भागीदारी चाहता है। वहीं, सपा की नजर विशेषकर आरक्षित सीटों पर है, जहां उसे लगता है कि बसपा के वोट बैंक का लाभ उसे मिल सकता है।

पूर्वांचल में राजनीति को बिरादरी की जमीन पर पहुंचाने की कोशिश जाति आधारित दल और विपक्ष कर रहा है। निषाद, कुर्मी, सैंथवार, राजभर जैसे वोट बैंकों को लेकर अपनी–अपनी दावेदारी है। इस राजनीति से पार पाने की चुनौती भाजपा के सामने है। विपक्ष के साथ ही उसे अपने सहयोगी दलों के दबाव से भी पार पाना है। ऐसे में गोरखपुर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े क्षेत्रीय संगठन से लेकर बूथ प्रबंधन तक पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसके बाद पार्टी रणनीति तय करेगी। तावड़े भाजपा के प्रमुख पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ मंथन करेंगे। तावड़े ने बिहार विधानसभा चुनाव में यह काम बखूबी किया था। वहीं, सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल भी गोरखपुर की दो सुरक्षित सीटों खजनी और बांसगांव में सम्मेलन कर पीडीए में दलितों के महत्व का संदेश देने में लगे हैं। बिरादरी के मतदाताओं को जोड़ने और तोड़ने की राजनीति निषाद वोट बैंक में सबसे साफ दिख रही है।प्रदेश सरकार में कैबिनेट रैंक के मंत्री होने के बावजूद वह लगातार दबाव बना रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पर सरकार के गंभीर न होने की स्थिति में राजनीतिक फैसला लेने का बयान दे रहे निषाद 14 सितंबर को सपा के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडेय से लखनऊ में मिले। यद्यपि संजय निषाद इसे शिष्टाचार भेंट बता रहे हैं, लेकिन यह मुलाकात राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय बन गई।

गोरखपुर क्षेत्र में वह लगातार सक्रिय हैं। उनकी पार्टी के सामाजिक आधार में सेंधमारी का प्रयास बिहार के मुकेश सहनी भी कर रहे हैं। वह अपने दल विकासशील इंसान पार्टी (वीआइपी) के जरिये आरक्षण को मुद्दा बना रहे हैं। वहीं, रामभुआल निषाद और पप्पू निषाद को लोकसभा भेज चुकी सपा भी निषाद मतदाताओं को साधने में जुटी है। कुर्मी मतदाताओं के दम पर अपना दल (एस) की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी एनडीए में ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही हैं। अनुप्रिया ने छह सितंबर को देवरिया के टाउनहाल में 2027 की तैयारी का आह्वान करने के साथ संगठन को गांव और बूथ तक मजबूत करने पर जोर दिया। इसी सामाजिक आधार से आने वाले सैंथवार अपनी अलग पहचान स्थापित करने का गंभीर प्रयास कर रहे हैं। सैंथवार समाज जाति प्रमाण पत्र में कुर्मी की जगह मल्ल के साथ वर्गीकरण चाहता है। पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर भाजपा कुर्मी मतदाताओं को संदेश देना चाहती है। सैंथवार समाज को साधने के लिए आरपीएन सिंह को भी सक्रिय किया गया है। वहीं, सपा नरेश उत्तम पटेल, लालजी वर्मा के अलावा बस्ती के सांसद राजेंद्र चौधरी के भरोसे इस वोट बैंक में अपनी पैठ को मजबूत करना चाहती है। खजनी–बांसगांव की आरक्षित सीटों पर लगातार दो दिन सम्मेलन और संगठन के निचले ढांचे की भागीदारी से सपा पिछड़ा–दलित आधार मजबूत करने में लगी है। अगले महीने अखिलेश यादव के प्रस्तावित दो दिवसीय गोरखपुर कार्यक्रम की तैयारियां भी इसी क्रम में आगे बढ़ रही हैं।

गोरखपुर के रास्ते न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी पूजा स्पेशल

यह ट्रेन गोरखपुर के रास्ते नौ फेरों में चलेगी
4 अक्टूबर से 30 नवंबर तक होगी इसकी सेवा

संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में लखनऊ से न्यू जलपाईगुड़ी तक आवागमन करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार 05742 / 05741 नंबर की न्यू जलपाईगुड़ी–गोमती नगर–न्यू जलपाईगुड़ी वाया गोरखपुर साप्ताहिक त्योहार स्पेशल नौ फेरा में चलेगी।

यह ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से 04 अक्टूबर से 29 नवम्बर तक प्रत्येक रविवार को तथा गोमती नगर से 05 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी। इस ट्रेन में सामान्य द्वितीय श्रेणी के 20 कोच लगाए जाएंगे। 05742 नंबर की न्यू जलपाईगुड़ी–गोमती नगर साप्ताहिक स्पेशल न्यू जलपाईगुड़ी से सुबह 08.30 बजे प्रस्थान करेगी।

यह ट्रेन सिलीगुड़ी, पूर्णिया, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, छपरा होते हुए गोरखपुर से रात 02:20 बजे रवाना होकर दूसरे दिन सुबह 09:10 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी। 05741 नंबर की गोमती नगर–न्यू जलपाईगुड़ी साप्ताहिक स्पेशल गोमतीनगर से दोपहर 12.20 बजे प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन अयोध्या धाम, बस्ती होते हुए गोरखपुर से रात 21.15 बजे रवाना होकर देवरिया, सीवान, छपरा, मुजफ्फरपुर और कटिहार होते हुए दूसरे दिन दोपहर बाद 03:00 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी।

अब कचरे का कचूमर निकालेगा स्मार्ट बिन

रेलवे बोर्ड ने स्मार्ट बिन लगाने की प्रायोगिक अनुमति दी
ये बिन कचरे को दबाकर उसकी मात्रा कम करेंगे
स्टेशनों पर स्वच्छता और कचरा प्रबंधन बेहतर होगा

गोरखपुर,संवाददाता। बड़े रेलवे स्टेशनों पर पारंपरिक कूड़ेदान (डस्टबिन) की जगह वेस्ट कांपेक्टर स्मार्ट बिन लगाया जाएगा। यह आधुनिक पात्र कचरे को स्वतरू दबाकर उसकी मात्रा कम करेगा। यानी जितना कचरा, उतनी जगह की जरूरत नहीं होगी। इससे कूड़ेदान जल्दी भरने और कचरा बाहर फैलने की समस्या कम होगी। रेलवे बोर्ड ने 16 सितंबर को सभी जोनल रेलवे को पत्र भेजकर स्थानीय परिस्थितियों और परिचालन जरूरतों के अनुसार स्मार्ट बिन की उपयोगिता का आकलन करने तथा प्रायोगिक आधार पर इन्हें लगाने की अनुमति दी है। खासकर अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर यह तकनीक उपयोगी होगी, जहां पारंपरिक डस्टबिन सीमित क्षमता के कारण जल्दी भर जाते हैं। कचरे को मौके पर ही दबाकर उसकी मात्रा घटाने से उसे उठाने और निस्तारण की जरूरत भी अधिक व्यवस्थित होगी। सफाईकर्मियों को बार–बार डस्टबिन खाली करने की जरूरत कम पड़ेगी और स्टेशन परिसर में स्वच्छता बनाए रखना आसान होगा। चल रहे श्स्वच्छता ही सेवाश अभियान के तहत रेलवे की नई पहल कचरा प्रबंधन की दिशा में महत्वपूर्ण होगी।

ज्वाइंट डायरेक्टर अमिता भल्ला का कहना है कि रेलवे बोर्ड की इस पहल का मुख्य उद्देश्य स्टेशनों पर कचरे के ओवरफ्लो को कम करना, सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाना और ठोस कचरे के प्रबंधन में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाना है। वेस्ट कांपेक्टर स्मार्ट बिन में इन बिल्ट कांपेक्शन सिस्टम होगा, जिससे जमा कचरे का आयतन कम किया जा सकेगा।

इससे कम जगह में अधिक कचरा एकत्र किया जा सकेगा और डस्टबिन के जल्दी भरने की समस्या कम होने की उम्मीद है। रेलवे ने ऐसे स्थानों पर इनके इस्तेमाल को उपयुक्त माना है, जहां सूखे कचरे की मात्रा अधिक होती है। बाजार में उपलब्ध स्मार्ट बिन में कई आधुनिक सुविधाएं हो सकती हैं। इनमें सोलर पावर से संचालन, फिल लेवल मानीटरिंग सेंसर, आटोमेटेड अलर्ट, टच फ्री आपरेशन और डिजिटल मानीटरिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। इनसे बिन के भरने की स्थिति की निगरानी और समय पर कचरा उठाने की व्यवस्था को बेहतर किया जा सकता है। ज्वाइंट डायरेक्टर ने स्मार्ट बिन की स्थापना के बाद उनके प्रदर्शन और वास्तविक लाभों की निगरानी करने को कहा है।

गोरखपुर हत्याकांड का खुलासा–पट्टीदारी के युवक ने की थी शुभम की हत्या



शुभम की हत्या का पुलिस ने किया पर्दाफाश।
अवैध संबंध के संदेह में पट्टीदारी का युवक गिरफ्तार।
आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद।

संवाददाता, गोरखपुर। व्यापारी के बेटे कार्तिकेय मिश्र उर्फ शुभम की हत्या का बांसगांव थाना पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस के अनुसार पट्टीदारी के ही एक युवक ने अवैध संबंध के संदेह में शुभम की धारदार हथियार से हत्या की थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस हत्या के पीछे के घटनाक्रम और आरोपित के संदेह से जुड़े तथ्यों की भी पड़ताल कर रही है। जयंतीपुर गांव का रहने वाला 20 वर्षीय शुभम बीएससी प्रथम वर्ष का छात्र था। बुधवार की रात में घर से करीब 100 मीटर दूर बरामदे में सो रहा था। गुरुवार की भोर में पांच बजे के करीब सिर पर प्रहार करके शुभम की हत्या कर दी गई। सुबह घटना की जानकारी होने पर गांव में सनसनी फैल गई थी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

पोस्टमार्टम में सिर पर धारदार हथियार से गंभीर चोट के निशान मिले थे। चचेरे भाई विवेकानंद मिश्र की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। हत्या के बाद पुलिस ने घटना से पहले शुभम के संपर्क में रहे लोगों की जानकारी जुटानी शुरू की। करीब 17 लोगों से पूछताछ की गई। इनमें वे लोग भी शामिल थे, जिनसे घटना से 24 घंटे पहले शुभम की फोन पर बातचीत हुई थी।

गांव के कुछ युवकों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की गई और मोबाइल की काल डिटेल, बातचीत तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों की पड़ताल की गई। इसी जांच में पट्टीदारी के युवक पर संदेह गहराया और पूछताछ के बाद हत्या की कड़ी सामने आई। पुलिस के अनुसार आरोपित को शुभम के पट्टीदारी की एक महिला से अवैध संबंध होने का संदेह था।

इसी को लेकर उसके मन में रंजिश थी। इसी संदेह में उसने हत्या कर दी। आरोपित की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। घटना के समय शुभम के पिता स्वदेश मिश्र,मां सुधा मिश्रा उपचार के सिलसिले में लखनऊ में थे। पिता का पीजीआइ में किडनी प्रत्यारोपण हुआ था।

गैंग्सटर से भी चल रही थी पूछताछ

पुलिस ने हत्या की जांच में पुराने विवाद और संपर्कों को भी खंगाला था। परिवार को वर्ष 2021 में 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का मामला भी सामने आया था, जिसमें गैंगस्टर टिक्का सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था और परिवार को पुलिस सुरक्षा मिली थी। घटना के बाद पुलिस ने टिक्का को हिरासत में लेकर जांच की लेकिन कोई भूमिका नहीं मिली। इसके बाद रंगदारी के प्रकरण को अलग रखते हुए पुलिस ने शुभम के व्यक्तिगत संपर्क और घटना से पहले की गतिविधियों पर भी फोकस किया। हत्या के पर्दाफाश के बाद पुलिस अब आरोपित के बयान, बरामद हथियार और अन्य साक्ष्यों का मिलान कर रही है। पुलिस यह भी जांच रही है कि वारदात में आरोपित अकेला था या किसी अन्य व्यक्ति की भी कोई भूमिका रही है।

गोरखपुर रेलवे अस्पताल के बाहर चाय–पकौड़ी की दुकानों पर बिक रही उपचार पुस्तिका, गोपनीयता का खतरा

गोरखपुर,संवाददाता। ललित नारायण मिश्र केंद्रीय रेलवे अस्पताल (एलएनएम) गोरखपुर के बाहर असुरन चौराहा के पास चाय–पकौड़ी, पान–गुटखा व फोटो कापी की दुकानों पर धड़ल्ले से रेलकर्मियों की उपचार पुस्तिका और रेफरल फार्म बिक रहे हैं। असुरन चौराहा से यांत्रिक कारखाना के गेट तक लगभग सभी दुकानों के काउंटरों पर उपचार पुस्तिका और रेफरल फार्म रखे हुए हैं। दुकानदार, 30 से 50 रुपये में उपचार पुस्तिका तथा दो से पांच रुपये में रेफरल फार्म बेच रहे हैं। कहीं कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। दुकानों पर पुस्तिका और फार्म ही नहीं बिक रहे, बल्कि उन्हें भरने का भी कार्य किया जा रहा है। दुकानों पर बैठे लोग 50 से 100 रुपये लेकर भरने का भी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, सड़कों पर सजे साइबर कैफे में रेलवे की गोपनीयता भी भंग हो रही है। रेलकर्मी विशेषकर रिटायर्ड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (एचआरएमएस) पर छुट्टी, सुविधा पास और पीएफ आदि के आनलाइन आवेदन भी कैफे से ही करा रहे हैं। कैफे संचालक, बदले में मुंहमांगा कीमत वसूल रहे हैं। इसे सिस्टम की खामी कहें या रेलवे के विभागों की उदासीनता, जब से रेलवे के विभागीय कार्य आफलाइन (मैनुअल) से आनलाइन (एचआरएमएस) होने लगे हैं, तब से रेलकर्मियों से संबंधित गोपनीय रिकार्ड बाजार तक पहुंचने लगे हैं। हास्पिटल, कारखाना और इंजीनियरिंग आदि विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आनलाइन कार्य कार्यालय की जगह दुकानों से हो रहे हैं। मई 2026 में दीपक कुमार सिंह नाम के व्यक्ति ने यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में आनलाइन भर्ती का विज्ञापन निकाल दिया था। विज्ञापन में उसके एचआरएमएस पर दर्ज पहचानपत्र, पासवर्ड और अभिलेख आदि का उल्लेख था। गोपनीय रिकार्ड सोशल मीडिया में कैसे पहुंचा, यह सवाल है। दीपक के विज्ञापन पर 70 से 80 युवा कारखाने में इंटरव्यू देने पहुंच गए थे। फिलहाल, मामले की जांच पुलिस कर रही है।

गाजीपुर में 23 सितंबर को लगेगा रोजगार मेला

30 से ज्यादा कंपनियां करेंगी युवाओं का चयन



संवाददाता, गाजीपुर। रोजगार की तलाश में जुटे जनपद के युवाओं के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत सदर विधानसभा क्षेत्र में 23 सितंबर को वृहद रोजगार मेला आयोजित होगा।

जिला सेवायोजन कार्यालय और स्नातकोत्तर महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में मेला सुबह 10 बजे से महाविद्यालय परिसर में लगेगा।

इसमें 30 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं का चयन करेंगी।

सुरक्षा गार्ड, मशीन ऑपरेटर, हेल्पर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, सेल्स ऑफिसर, सुपरवाइजर, टेक्निशियन,

ऑपरेशन असिस्टेंट, ईवी तीन पहिया चालक और नैप्स ट्रेनी समेत विभिन्न पदों पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

हेल्पलाइन नंबर जारी

आठवीं, 10वीं, 12वीं, स्नातक–परास्नातक, आईटीआई, डिप्लोमा, एएनएम, जीएनएम, जीडीए और कौशल प्रशिक्षित अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीयन कर इच्छित कंपनियों में आवेदन करना होगा। मेले में मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र व छायाप्रति के साथ पहुंचना होगा। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन 155330 या जिला सेवायोजन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन



गोंडा,संवाददाता। कलेक्ट्रेट के टिनशेड में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने मानदेय बढ़ाने और पोषण ट्रैकर में बदलाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदेश महामंत्री नीलम पांडेय ने बताया कि शासन की ओर से कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 और सहायिकाओं के मानदेय में 750 रुपये की वृद्धि की गई है। इसके अलावा कार्यकर्ताओं को 2500 और सहायिकाओं को 1250 रुपये पीएलआई दिया जा रहा है। इससे कुल मानदेय 12 हजार और छह हजार रुपये है। संगठन ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को संविदा परिषद में शामिल करने के साथ पीएलआई से अलग न्यूनतम मानदेय 18 हजार रुपये करने की मांग की। इसके अलावा पोषण ट्रैकर में जीपीएस व्यवस्था से कार्यकर्ताओं को तकनीकी और व्यावहारिक दिक्कतें होने का दावा करते हुए इसे पूर्व की तरह बिना जीपीएस संचालित कराने की मांग की गई।

इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश दीक्षित, मंडल संरक्षक राजेश श्रीवास्तव, मंडल अध्यक्ष दीपा तिवारी, जिलाध्यक्ष प्रेम कुमारी यादव, जिला संयोजक संगम लाल शर्मा और महामंत्री नीरा जायसवाल आदि मौजूद रहे।

अलीगढ़ स्काई ब्ल्यू होटल में देह व्यापार

रुपयों के लालच में जिस्म का सौदा कर रही थी युवतियां, सात को जेल

संवाददाता, अलीगढ़। स्काई ब्ल्यू ओयो होटल में कथित अनैतिक देह व्यापार के मामले में गिरफ्तार होटल संचालक समेत सात आरोपितों को जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने सभी के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

ुक्रवार को हुई कार्रवाई के बाद पुलिस आरोपितों को न्यायालय में पेश करने की तैयारी में जुटी रही।

थाना छर्रा पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में शाह आलम निवासी बाइकला, थाना छर्रा, रंजीत सिंह बघेल निवासी नगौरा, थाना जवां, प्रकाश निवासी जरगवा, थाना रामघाट, बुलंदशहर, लक्ष्मीकांत राजपूत निवासी राजमार्गपुर, थाना अतरौली, होटल संचालक योगेंद्र राजपूत और आकाश राजपूत निवासी बरौली, थाना छर्रा तथा प्रदीप निवासी मोहम्मदपुर नाहर, थाना जहांगीरपुर, बुलंदशहर शामिल हैं।

स्काई ब्ल्यू होटल देह व्यापार मामले में सात आरोपित आज भेजे जाएंगे जेल

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 7,560 रुपये, छह मोबाइल फोन, 11 आधार कार्ड, गेस्ट एंट्री रजिस्टर, होटल के कैमरों की डीवीआर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार, होटल में युवतियों को रुपयों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कराने और अवैध धन कमाने का आरोप है।

रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की जांच

क्षेत्राधिकारी छर्रा गर्वित सिंह के अनुसार, मामले में होटल संचालक द्वारा युवकों से एक से डेढ़ घंटे के लिए 700 रुपये लेकर कमरा उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस गतिविधि में और कौन–कौन लोग शामिल हैं। मौके से मिली सात युवतियों को उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

युवतियों को रुपयों का लालच देकर धकेला इस धंधे में

पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 7,560 रुपये, छह मोबाइल फोन, 11 आधार कार्ड, गेस्ट एंट्री रजिस्टर, होटल के कैमरों की डीवीआर और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार, होटल में युवतियों को रुपयों का लालच देकर अनैतिक देह व्यापार कराने और अवैध धन कमाने का आरोप है।

रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की जांच

क्षेत्राधिकारी छर्रा गर्वित सिंह के अनुसार, मामले में होटल संचालक द्वारा युवकों से एक से डेढ़ घंटे के लिए 700 रुपये लेकर कमरा उपलब्ध कराने की बात सामने आई है। पुलिस यह पता लगा रही है कि इस गतिविधि में और कौन–कौन लोग शामिल हैं। मौके से मिली सात युवतियों को उनके स्वजन के सुपुर्द कर दिया गया है।

मुरादाबाद होमगार्ड भर्ती दौड़ में पांच अभ्यर्थी गिरे

हुई मौत के बाद शनिवार को फिर हुई घटना

होमगार्ड भर्ती दौड़ में पांच अभ्यर्थी गश खाकर गिरे

दो अभ्यर्थियों के पैर में फ्रैक्चर, तीन को मिली छुट्टी

संवाददाता, मुरादाबाद। होमगार्ड भर्ती दौड़ में शुक्रवार को दौड़ते हुए गिरकर हुई अभ्यर्थी की मौत के बाद शनिवार को पांच अभ्यर्थी दौड़ते हुए गश खाकर गिर गए। पांचों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। दो के पैर में फ्रैक्चर हो गया। जबकि तीन को उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है।

होमगार्ड भर्ती दौड़ के पांचवें दिन 1050 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। जिसमें से 995 अभ्यर्थी पहुंचे। जिसमें से 890 ने समय पर दौड़ पूरी कर ली। जबकि 105 अभ्यर्थी समय पर दौड़ पूरी नहीं कर पाए। जिसके चलते उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया। पांच अभ्यर्थी गश खाकर गिरे।

एसपी क्राइम व भर्ती के नोडल अधिकारी सुभाषचंद्र गंगवार ने बताया कि तीन अभ्यर्थियों को जिला अस्पताल के बाद उपचार से डिस्चार्ज कर दिया गया है। दो के पैर में फ्रैक्चर हुआ है। उनका उपचार चल रहा है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों की हो जाएगी बल्ले–बल्ले

संवाददाता, सहारनपुर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों को किशाऊ बांध परियोजना से यहां पूर्वी यमुना नहर को पूरे वर्ष भरपूर पानी मिल सकेगा। नहर में रबी सीजन के दौरान पानी का प्रवाह केवल 40 प्रतिशत तक रह जाता है, जिससे खेतों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता।

किशाऊ परियोजना से जुड़ी लखवार और रेणुका बांध के लिए यूपी द्वारा अपने हिस्से की 717 करोड़ से अधिक राशि मार्च में दी गई थी। सहारनपुर के बड़े भूभाग में खेतों की सिंचाई पूर्वी यमुना नहर से होती है।

खेती के लिए वर्ष भर पर्याप्त पानी मिलेगा

किशाऊ बांध परियोजना साकार होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से किसानों को खेती के लिए वर्ष भर पर्याप्त पानी सुलभ हो सकेगा। यमुना नदी से सहारनपुर की पूर्वी यमुना नहर में पानी छोड़ा जाता है। सिंचाई विभाग के अनुसार रबी सीजन के दौरान अक्टूबर से मार्च तक नहर में पानी का प्रवाह केवल 40 प्रतिशत तक रह जाता है, जिस कारण किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता और ट्यूबवेल पर निर्भरता बढ़ जाती है।

यूपी ने दी 717 करोड़ से अधिक की राशि

पूर्वी यमुना नहर के पानी से सहारनपुर के बाद शामली, बागपत और गाजियाबाद के किसानों को लाभ मिलता है। विभाग के अनुसार किशाऊ बांध परियोजना के साथ ही लखवार और रेणुकाजी परियोजना से जुड़ी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में निर्माणाधीन दो जल परियोजनाओं लखवार और रेणुका जी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी के रूप में मार्च–2026 में 717 करोड़ से अधिक की राशि प्रदेश सरकार द्वारा सिंचाई माध्यम से इन राज्यों को भेजी गई थी।

पहले करते थे रेकी, फिर बंद घरों का तोड़ते थे ताला, चार आरोपी गिरफ्तार

लखनऊ,संवाददाता। बंद मकानों की रेकी कर ताला तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का पवई पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पवई पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में मोहम्मद अब्दुल्ला निवासी सठियांव, अंबेश कुमार निवासी कुकुड़ीपुर सठियांव, आकाश कुमार निवासी गजाड़ा सठियांव और विकास सोनी निवासी सरायमीर को गिरफ्तार किया गया है।

इनके कब्जे से करीब 5.50 लाख रुपये कीमत के 14 सोने और 22 चांदी के आभूषण, 14 हजार रुपये नकद, तमंचा–कारतूस, एक टेंपो और दो मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। आरोपियों ने आजमगढ़ के चार थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था। पुलिस का दावा है कि आरोपियों ने आजमगढ़ के चार थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया था।

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि आरोपी ऐसे मकानों को निशाना बनाते थे जिनके मालिक या परिवार के सदस्य घर से बाहर गए होते थे। पहले मकान की रेकी करते और मौका मिलते ही ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो जाते थे।

इसके बाद सोने–चांदी के आभूषण और नकदी लेकर फरार हो जाते थे। 12 सितंबर को पवई थाना क्षेत्र के नाटी गांव निवासी उमाशंकर अपनी पत्नी के साथ अंत्येष्टि में शामिल होने गए थे। उनके बच्चे स्कूल गए थे।

इसी दौरान अज्ञात चोरों ने घर का ताला तोड़कर सोने–चांदी के आभूषण, नकदी और जमीन से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात चोरी कर लिए थे। एसपी डॉ. अनिल कुमार ने घटना के शीघ्र खुलासे के लिए पुलिस की तीन टीमें गठित की थीं।

शुक्रवार की सुबह करीब पांच बजे पवई पुलिस और एसओजी–सर्विलांस टीम ने अंबारी रोड पर बाबर पुलिया से करीब 100 मीटर आगे घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी की चार घटनाओं का खुलासा किया।

चोरी का सामान खरीदने वाला भी गिरोह में शामिल हो गया

एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि 24 जुलाई को कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मस्थान में मकान का ताला तोड़कर जेवर और 25 हजार रुपये, चार अगस्त को रौनापार के सिसनीपर में, 26 अगस्त को अहरौला के पकड़ी में और 12 सितंबर को पवई के नाटी गांव में चोरी की गई थी। पूछताछ में पता चला कि विकास सोनी पहले चोरी का सामान खरीदता था। बाद में वह गिरोह के साथ चोरी की घटनाओं में शामिल होने लगा। आरोपी चोरी किए गए सामान को अंबेडकरनगर में बेचने की योजना बना रहे थे। घटना में प्रयुक्त हरे रंग का टेंपो और दो मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं।

आजमगढ़ और मऊ में दर्ज हैं मामले

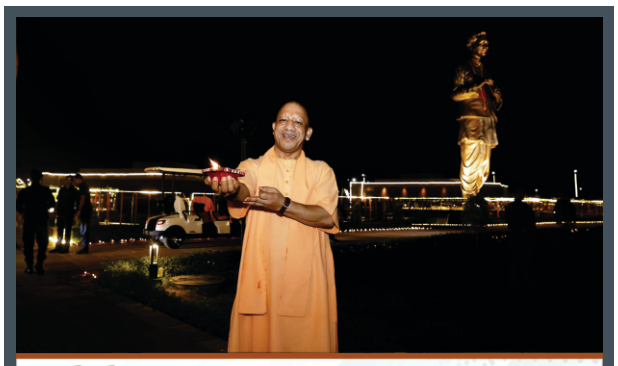
एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि मोहम्मद अब्दुल्ला के खिलाफ आजमगढ़ और मऊ के विभिन्न थानों में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट और आर्म्स एक्ट समेत कई प्राथमिकी दर्ज हैं। अंबेश कुमार के खिलाफ भी आजमगढ़ और मऊ में पूर्व के कई मामले दर्ज बताए गए हैं। अन्य आरोपियों के खिलाफ भी संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

नौ पदकों के साथ टाउन नेशनल इंटर कालेज बना ओवरआल चैंपियन



गाजीपुर,संवाददाता। जग नारायण इंटर कॉलेज, बीरपुर के नेतृत्व में शहर के मिश्रबाजार स्थित राजकीय सिटी इंटर कॉलेज के रणदीप सभागार में 70वीं जनपदीय माध्यमिक विद्यालयी बालक व बालिका योग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। कुछ नौ पदकों के साथ टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर प्रतियोगिता के ऑल ओवर चौंपियन का खिताब अपने नाम किया।

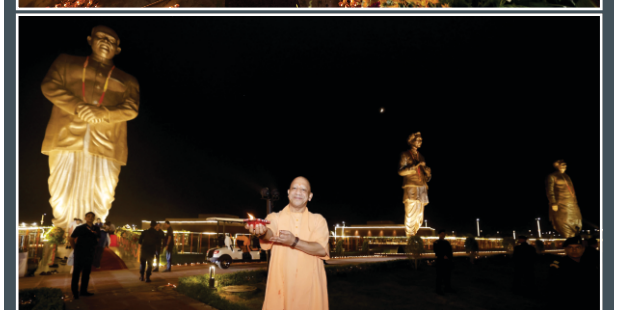
जिला क्रीड़ा सचिव आकाश सिंह ने बताया कि टाउन नेशनल इंटर कॉलेज सैदपुर ने सात स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ प्रथम स्थान पर रही। वहीं, बापू इंटर कॉलेज सादात चार स्वर्ण और दो रजत पदक के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। श्री बेनी सिंह इंटर कॉलेज लच्छीपुर दौलतपुर और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सैदपुर संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। अंत में मुख्य अतिथि डीआईओएस श्री प्रकाश सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित कर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि विनय गुप्ता, सिटी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य दिनेश यादव, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य शालिनी श्रीवास्तव, माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मंत्री चौधरी दिनेश चंद्र राय, पर्यवेक्षक शिवशंकर गिरि आदि मौजूद रहे।



आशीर्वाद के इस दीये के साथ **राष्ट्र प्रेरणा स्थल** पर जगमगाते लाखों दीपक, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की प्रेरणा से, **विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश** तथा **आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश** के संकल्प के साथ जुड़ने का आह्वान कर रहे हैं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश









राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गरिमामयी उपस्थिति में जन भवन, लखनऊ में 'गंगासागर नमो नमः का लोकार्पण हुआ।



26 ग्लोबल कंपनियां यूपी में जीसीसी में करेंगी निवेश

लखनऊ,संवाददाता। 1710 करोड़ रुपये के निवेश वाले चार प्रस्तावों को उच्चस्तरीय समिति की मंजूरी मिल चुकी है। ये कैबिनेट अनुमोदन अथवा लेटर ऑफ कम्फर्ट चरण में हैं। 14 मामले डीपीआर स्तर पर हैं, जिनमें 1223 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। उत्तर प्रदेश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) के कई हब विकसित करने की तैयारी है। औद्योगिक विकास विभाग ने 2000 से अधिक कंपनियों से संपर्क चुना है। इनमें तत्काल निवेश के लिए 26 कंपनियां चुनी गई हैं। इनसे 3936 करोड़ रुपये के निवेश और 22 हजार रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। विभाग जमीन, कार्यालय विश्वविद्यालयों व निजी क्षेत्र के सहयोग से प्रतिभा ढांचा विकसित कर रहा है। वहीं, 25 विश्वविद्यालयों से एमओयू कर पूर्व छात्रों के डाटा से टैलेंट पूल बनेगा।

चार प्रस्ताव अंतिम चरण में – अमेजन,



माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, ऑप्टम और बार्कलेज एंकर जीसीसी हैं। एलजी, अमेरिप्राइज, एओएन, मेटलाइफ और टेबल स्पेस से बातचीत चल रही है। एडोबी, फिसर्व और ईएक्सएल समेत 150 जीसीसी कंपनियां संभावित लक्ष्य समूह में हैं। 1710 करोड़ रुपये के निवेश वाले चार प्रस्तावों को उच्चस्तरीय समिति की मंजूरी मिल चुकी है। ये कैबिनेट अनुमोदन अथवा लेटर ऑफ कम्फर्ट चरण में हैं। 14 मामले डीपीआर स्तर पर हैं, जिनमें 1223 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है। दो मामलों में जमीन की अड़चन है।नोएडा में विस्तार की तैयारीः नोएडा में 169 जीसीसी संचालित हैं। यहां 12 विकल्पों में 24.6 मिलियन वर्ग फुट ग्रेड–ए स्पेस मैप किया गया है। 26.9 लाख वर्ग फुट तत्काल उपलब्ध है। किराया 65 से 85 रुपये प्रति वर्ग फुट प्रतिमाह है। सेक्टर–127 में 57 फीसदी जगह है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 167 एकड़ जमीन जीसीसी के लिए तैयार है। इसमें नोएडा के वाणिज्यिक भूखंडों की 37.4, ग्रेटर नोएडा की 77 और 52.8 एकड़ जमीन शामिल है। 10.1 लाख वर्ग फुट तैयार किराये की जगह चिह्नित है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर प्रदेश की मेधा को रोकने और बाहर से प्रतिभा लाने में मील का पत्थर साबित होंगे। तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ वेतन मिलेगा। जल्द परिणाम आएंगे।

सुल्तानपुर व अमेठी सहित 14 जिलों में खुलेंगे नर्सिंग कालेज

एक जिला एक मेडिकल कालेज की तर्ज पर बना प्लान

लखनऊ,संवाददाता। यूपी में 14 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने को लेकर शासन ने मंजूरी दे दी है। इससे प्रदेश में नर्सिंग की 840 सरकारी सीटें बढ़ेंगी। इनका संचालन शैक्षिक वर्ष 2027–28 से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश में 14 नए राजकीय नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। इन्हें स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में संचालित किया जाएगा। हर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 60–60 सीटें होंगी। इससे प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की करीब 840 सीटें बढ़ेंगी। प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज खोलने की रणनीति बनाई है। प्रदेश में अभी 23 कॉलेजों में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई हो रही है। इनमें करीब 1400 सीटें हैं। 235 निजी नर्सिंग कॉलेजों में करीब 11 हजार सीटें हैं। प्रदेश सरकार की ओर से अगस्त माह में नर्सिंग कॉलेज बढ़ाने की योजना तैयार की गई। शासन ने 14 जिलों में राजकीय नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दे दी है। हर कॉलेज में बीएससी नर्सिंग की 60–60 सीटें होंगी। इनका संचालन शैक्षिक वर्ष 2027–28 से शुरू होगा।

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय में होगा संचालन : नए खुलने वाले नर्सिंग



कॉलेजों के संचालन की जिम्मेदारी स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों को सौंपी गई है। सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया गया है कि वे पाठ्यक्रम संचालन के लिए नियामक संस्थाओं के आदेश एवं निर्देश और मानकों का अध्ययन कर लें। उनका हर हाल में पालन किया जाए। इन जिलों में खुलेंगे रू मिर्जापुर, हरदोई, प्रतापगढ़, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अमेठी, सुल्तानपुर, एटा, गाजीपुर, पुर, सोनभद्र, कौशांबी, शांबी, ललितपुर, लखीमपुर खीरी और बिजनौर के चिकित्सा महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को नर्सिंग कॉलेज खोलने की मंजूरी दी गई है। विभागीय सूत्र बताते हैं कि जल्द ही अन्य स्वशासी महाविद्यालयों में भी नर्सिंग कॉलेजों को खोलने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

होमगार्ड भर्ती की दौड़ में अभ्यर्थी की मौत

अचानक बेहोश होकर गिरा शिवम बीटेक की पूरी की थी पढ़ाई

मुरादाबाद,संवाददाता। मुरादाबाद में होमगार्ड भर्ती की दौड़ के दौरान बरेली निवासी शिवम यादव अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मुरादाबाद में 9वीं वाहिनी पीएसी मैदान में चल रही होमगार्ड भर्ती की दौड़ के दौरान शुक्रवार सुबह एक अभ्यर्थी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। अभ्यर्थी को आनन–फानन में जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उसकी पहचान शिवम यादव पुत्र विनोद यादव निवासी राजपुर कला, मणिनाथ कॉलोनी बरेली निवासी के तौर पर हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुबह करीब आठ बजे दौड़ के दौरान शिवम अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। भर्ती प्रक्रिया में मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।शिवम के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है।

उनके परिवार में पत्नी कोमल और तीन साल की बेटी है। बताया गया कि शिवम ने बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और घर पर ही बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर परिवार का पालन–पोषण करते थे। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मातम छा गया।

टीएमसी के दोनों गुटों को मिले चुनाव चिह्न

ममता बनर्जी को फुटबाल खिलाड़ी

नई दिल्ली,एजेंसी। निर्वाचन आयोग ने टीएमसी के ममता बनर्जी और ऋतब्रत बनर्जी गुटों को नए नाम और चुनाव निशान सौंप दिए हैं। इससे पहले आयोग ने दोनों दलों की बारी–बारी से सुनवाई की थी। दोनों दलों को क्या नए नाम और निशान मिले हैं। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दोनों गुटों के लिए नए नाम और चुनाव चिह्न आवंटित कर दिए हैं। ममता गुट को ममता अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस नाम और चुनाव चिह्न फुटबॉल खिलाड़ी मिला है। पार्टी सूत्रों ने यह जानकारी दी। वहीं, ऋतब्रत बनर्जी से जुड़े प्रतिद्वंद्वी गुट को डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस नाम आवंटित किया गया है। निर्वाचन आयोग की ओर से साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस गुट को लिफाफा चुनाव चिह्न दिया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने शुक्रवार को निर्वाचन आयोग को नए चुनाव चिह्न सुझाए। इनमें क्रिकेट बैट शामिल था। बिना गेंद वाले फुटबॉलर का चिह्न भी सुझाया गया था। साथ ही पार्टी के लिए तीन नाम भी प्रस्तावित किए गए थे।

जांच में मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त

गवाहों के बयान की आडियो–वीडियो रिकार्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करें डीजीपी

प्रयागराज,संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत गवाहों के बयान की ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार किया जाए। अदालत ने कहा कि इससे जांच में मनमानी की गुंजाइश कम होगी और जमानत समेत अन्य न्यायिक कार्यवाहियों में भी मदद मिलेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को गवाहों के बयान की ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य करने पर विचार करने को कहा है। न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की एकल पीठ ने कहा कि इससे जांच प्रक्रिया अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी होगी। साथ ही अदालतों को जमानत अर्जी और अन्य न्यायिक कार्यवाहियों में भी मदद मिलेगी।

अदालत ने यह आदेश आगरा के बसौनी थाने में दर्ज दहेज हत्या के मामले में चंद्रकांता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दिया। सुनवाई के समय विवेचक सहायक पुलिस आयुक्त अनिल कुमार अदालत में मौजूद थे। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रथम सूचनाकर्ता का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के तहत दर्ज करते समय उसकी ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी। बाद में विवेचक ने अदालत के समक्ष बिना शर्त माफी भी मांगी।

कई मामलों में बयान लिखने की प्रक्रिया पर उठे सवाल

हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 180 की उपधारा (3) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नियमावली, 2024 के नियम 20(1) के तहत विवेचक को गवाहों के बयान ऑडियो–वीडियो माध्यम से दर्ज करने की अनुमति है। जुलाई 2025 में पुलिस महानिदेशक की ओर से जारी परिपत्र में दुष्कर्म पीड़िता के बयान की ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य की गई थी, जबकि अन्य मामलों में इसे वैकल्पिक रखा गया था। अदालत ने कहा कि उसने ऐसे कई मामले देखे हैं, जिनमें विवेचकों ने उपलब्ध सुविधा के बावजूद गवाहों के बयान की ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। अदालत के अनुसार, इससे यह आरोप लगने की आशंका रहती है कि बयान विवेचक ने स्वयं तैयार किया है या प्राथमिकी में लिखी बातों को ही बयान के रूप में दर्ज कर दिया गया है।

तुम मेरे हो–ईशा मालवीय की बालीवुड में एंट्री

गुरमीत चौधरी संग करेंगी रोमांस



एंटरटेनमेंट डेस्क। ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी स्टारर फिल्म तुम मेरे हो के नए पोस्टर सामने आए हैं। साथ ही फिल्म की रिलीज डेट का भी ऐलान हो गया है। आइए जानते हैं कि ये मूवी कब आने वाली है। बिग बॉस 17 फेम ईशा मालवीय जल्द फिल्म तुम मेरे हो के साथ बॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। गुरुवार को मेकर्स ने उनकी इस हिंदी फिल्म के कई पोस्टर जारी किए। खास बात ये है कि इस मूवी में वह टीवी के पॉपुलर अभिनेता गुरमीत चौधरी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए दिखाई देंगी।

कैसे हैं ईशा और गुरमीत की फिल्म के पोस्टर

गुरमीत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर फिल्म के पोस्टर शेयर किए हैं, जिसमें देखने को मिला कि दोनों रोमांस में खोए हुए नजर आ रहे हैं। पहले पोस्टर में दोनों लिपलॉक करते नजर आए और आगे के पोस्टर में भी दोनों का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला।

कब रिलीज होगी फिल्म तुम मेरे हो

इन पोस्टर को करते हुए अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, श्तुम मेरे होश की दुनिया में डुबकी लगाओ। फिल्म 23 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। क्योंकि कई बार, प्यार में पड़ना आसान होता है, लेकिन इसके बाद जो होता है, वो कहानी है। बता दें कि गुरमीत चौधरी ही ईशा को बॉलीवुड में लॉन्च कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन आशीष पांडा ने किया है और यह रेवा क्रिएटिव हाउस और देबगुरु फिल्म्स के बैनर तले बनाई गई है। वहीं, फिल्म को आरती एस और देबिना बनर्जी ने प्रोड्यूस किया है। तरण आदर्श के मुताबिक, मूवी में लव स्टोरी के साथ–साथ एडवेंचर और एक्शन भी देखने को मिलेगा। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ईशा मालवीय और गुरमीत चौधरी की केमिस्ट्री लोगों को पसंद आती है या नहीं।

भारत से आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुनी गई यह मराठी फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, मराठी फिल्म गोंधल को ऑस्कर 2027 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के तौर पर चुना है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी। इस फिल्म के निर्देशक, लेखक और निर्माता संतोष दवाखर हैं। यह फिल्म 14 नवंबर 2025 को रिलीज हुई थी। इसका टीजर कांतारा चौप्टर 1 के साथ रिलीज हुआ था। साउथ के महान संगीतकार इलैयाराजा ने इसका संगीत दिया है।

कैसी है फिल्म की कहानी?

संतोष दवखर द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके पर आधारित है और इसकी कहानी एक नवविवाहित जोड़े से जुड़ी पारंपरिक रस्म वाली एक रात के इर्द–गिर्द घूमती है। सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन पी. शेषद्रि ने बताया कि ऑस्कर 2027 के लिए 33 फिल्मों की लिस्ट में से इस फिल्म को चुना गया।

कितनी फिल्मों से था मुकाबला?

ऑस्कर की 2027 की एंट्री के लिए कुल 33 फिल्में सबमिट की गई थीं, जिनमें से 14 हिंदी में थीं। मराठी, तेलुगु और गुजराती में चार–चार फिल्में थीं। तीन फिल्में तमिल में और एक–एक फिल्म मलयालम और नागामीज भाषा में थीं। इनमें एक साइलेंट फिल्म भी शामिल थी। हालांकि आधिकारिक एंट्री के लिए गोंध को चुना गया।

गुल्लू बने घर के नए कैप्टन, किस बात पर भिड़े माही और मैरी काम



एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस 20 अपडेट्स– बिग बॉस 20 से नए प्रोमो सामने आए हैं, जिन्हें देखकर फैंस की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। जहां एक तरफ गुल्लू को कैप्टन बनाया गया है। वहीं, दूसरी तरफ मैरी कॉम और माही के बीच जमकर हंगामा देखने को मिला है। जानिए प्रोमो में और क्या है खास। बिग बॉस 20 के घर में इन दिनों खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। घरवालों के बीच लगातार नए समीकरण बन रहे हैं और पुराने रिश्तों में भी दरार आती नजर आ रही है। इसी बीच कुशाल तंवर उर्फ गुल्लू घर के नए कैप्टन बन गए हैं।

गुल्लू बने घर के नए कैप्टन

कैप्टेंसी टास्क में गुल्लू के साथ माही विज, कनिका मान और रिति तिवारी ने हिस्सा लिया। टास्क के दौरान घरवालों को नॉमिनेटेड सदस्यों की लाइफलाइन छीनने की पावर दी गई थी। गुल्लू ने स्काउट ओपी की लाइफलाइन छीनी, जबकि कनिका ने रोहेड़ खान और माही ने आसिफ खान की लाइफलाइन अपने नाम की। आखिरकार गुल्लू को घर का नया कैप्टन चुन लिया गया।

माही और मैरी कॉम में क्यों हुई बहस?

दूसरी तरफ घर में माही विज और मैरी कॉम के बीच भी तीखी बहस देखने को मिली। सामने आए प्रोमो में दोनों के बीच सम्मान को लेकर बातचीत बढ़ती नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक, मैरी कॉम ने माही से कहा कि उनका प्रोफाइल काफी बड़ा है और उन्हें उनकी तुलना खुद से नहीं करनी चाहिए। इसके जवाब में माही ने पूछा कि वह उनकी बातों से इतना परेशान क्यों हो रही हैं। बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैरी कॉम ने माही से उन्हें सम्मान देने की बात कही, जिस पर माही ने सवाल किया कि वह उन्हें सम्मान क्यों दें। माही ने यह भी आरोप लगाया कि मैरी कॉम उनके बारे में पीठ पीछे बातें करती हैं और उनके मेकअप और कपड़ों को लेकर टिप्पणी करती हैं।

अरिश्फा से भिड़ीं लव गिल

वहीं लव गिल और अरिश्फा के बीच भी जमकर कहासुनी देखने को मिलने वाली है। एक और प्रोमो में दोनों के बीच बहस होती दिख रही है। अरिश्फा, लव को लेकर कुछ कह देती हैं, जिसके बाद लव काफी भड़क जाती हैं और आकर पूछती हैं, किसकी चमचागिरी कर रहे हैं।

इस पर अरिश्फा कहती हैं कि आपको क्या लगता है, हम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता, हम लोग बहरे हैं? इस पर लव कहती हैं– अंधे आगे अरिश्फा उन्हें बेटा कह देती हैं, तो गिल कहती हैं, ओ मां मत बन मेरी...बेटा क्या होता है? आगे अरिश्फा कहती हैं, श्मेरे से ना आप पंगे मत लेना। इसके बाद दोनों के बीच जमकर हंगामा होता है।

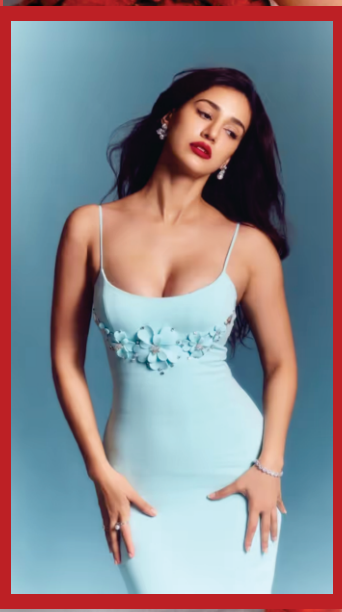
अरिश्फा खान पर भड़के स्काउट

एंटरटेनमेंट डेस्क। बग बॉस 20 के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हंगामा देखने को मिलने वाला है। रिलीज हुए नए प्रोमो को देखकर फैंस की एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है। जानिए वीडियो में क्या कुछ है खास। इन दिनों बिग बॉस 20 खूब चर्चा में है। हर दिन इसमें कुछ न कुछ नया हो रहा है। कभी कोई कॉमेडी करता है, तो कभी किसी से तीखी नोकझोंक देखने को मिलती है। इस बीच मेकर्स ने शो के कुछ नए प्रोमो शेयर किए हैं, जिसमें अलग लेवल का बवाल देखने को मिल रहा है।

क्यों हुई अरिश्फा और स्काउट के बीच लड़ाई

दरअसल, मेकर्स ने एक नया प्रोमो शेयर किया है। इसमें कप्तानी के लिए नया टास्क दिया जाता है, जहां लड़कियों को लड़कों पर कलर फेंकना होगा। इसके बाद दूसरे सीन में अरिश्फा खान और स्काउट गेम खेलते हुए नजर आते हैं। इस बीच अरिश्फा स्काउट के मुंह पर कलर फेंक देती हैं। इसके बाद स्काउट अरिश्फा को कुछ कहते हैं, तो उदिति बीच में आकर उनसे अरिश्फा को हाथ ना लगाने को कहती हैं। आगे जब एक बार और स्काउट के मुंह पर कलर लग जाता है, तो वो काफी गुस्सा हो जाते हैं, और जोर–जोर से चिल्लाने लगते हैं।

वहीं अरिश्फा भी इस दौरान गुस्से में नजर आती हैं। वीडियो के आखिर में स्काउट अपनी ऑडियंस से कहते हैं, श्आप लोगों ने देखा ही है, जो भी हुआ। मैं इस पॉइंट के बाद आपसे सबसे ज्यादा सपोर्ट की उम्मीद करता हूं।



शहनाज गिल ने क्यों ठुकराई हिंदी फिल्में

दिल्ली,एजेंसी। शहनाज गिल ने फिल्म 100: के बंद होने, बॉलीवुड में काम के लिए फीस और इज्जत की अहमियत, हिंदी फिल्मों में रोल के चुनाव और डायरेक्शन में अपने फ्यूचर प्लान पर खुलकर बात की है. शहनाज गिल ने क्यों ठुकराई हिंदी फिल्में? रोल्स को लेकर हसीना ने पहली बार किया खुलासा; बोलीं– 'सिर्फ पैसा नहीं, आत्म–सम्मान और इज्जत भी जरूरी'। फिल्ममेकर साजिद खान की फिल्म 100: से वापसी का ऐलान 4 साल पहले हुआ था, जिसमें शहनाज गिल के साथ जॉन अब्राहम, रितेश देशमुख और नोरा फतेही लीड रोल में नजर आने वाले थे. हालांकि, यह फिल्म कभी बन नहीं पाई. हाल ही में गिप्पी ग्रेवाल के साथ पंजाबी फिल्म सिंह वर्सेस कौर 2 में नजर आईं शहनाज गिल से जब इस फिल्म के डिब्बाबंद होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि वे इन चीजों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती हैं. उनका मानना है कि जो नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ, क्योंकि कुछ चीजें न बनने में ही भलाई होती है. जब तक प्रोजेक्ट पूरी तरह बनकर तैयार न हो जाए, तब तक उसकी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है. अगर कल को काम नहीं हुआ, तो लोग सवाल करेंगे और वे लोगों की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहतीं.

फ्री में काम करने और इंडस्ट्री में इज्जत पर क्या कहा?

शहनाज गिल ने हाल ही में एचटी सिटी से खुलासा किया था कि अतीत में रिश्तों के सम्मान में फ्री में काम करने की वजह से उन्हें इंडस्ट्री के अंदर से वह इज्जत नहीं मिली, जिसकी वे हकदार थीं. इस पर विस्तार से बात करते हुए उन्होंने बताया कि जब आप अपनी मेहनत के पैसे लेते हैं, तो वह बेहद जरूरी होता है. अगर आप पैसे नहीं लेंगे, तो आपकी और आपके काम की कोई इज्जत नहीं होगी और लोग आपको गंभीरता से नहीं लेंगे. उन्होंने बताया कि पहले कई म्यूजिक वीडियोज में उनके साथ ऐसा हो चुका है, लेकिन एक वक्त के बाद आपको ना कहना सीखना पड़ता है, क्योंकि यह केवल पैसों की बात नहीं, बल्कि आत्म–सम्मान और इज्जत की बात है।

नायर ने पीले कपड़ों पर ली रोहित की चुटकी



स्पोर्ट्स डेस्क। पीले कपड़ों में नजर आए रोहित शर्मा को अभिषेक नायर ने चेन्नई और कोलकाता की टीमों से जोड़कर मजाक किया। इस दौरान दर्शकों ने मुंबई–मुंबई के नारे लगाए, जिस पर रोहित के जवाब ने माहौल बना दिया। वहीं, उनके आईपीएल भविष्य और 2027 विश्व कप में खेलने को लेकर भी सवाल कायम हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा इन दिनों अपने नए टीवी शो फॅमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा को लेकर चर्चा में हैं। शो के एक टीजर में रोहित और उनके करीबी दोस्त व कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच अभिषेक नायर के बीच आईपीएल को लेकर मजेदार बातचीत देखने को मिली। नायर ने रोहित को पीले कपड़ों में देखकर पहले चेन्नई सुपर किंग्स और फिर कोलकाता नाइट राइडर्स से जोड़कर मजाक किया। हालांकि, जब दर्शकों ने श्मुंबई–मुंबईश के नारे लगाए तो रोहित के सिर्फ एक शब्द के जवाब ने मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों का दिल जीत लिया।

पीले कपड़ों में दिखे रोहित तो नायर ने ली चुटकी

शो के दौरान रोहित शर्मा पूरी तरह पीले रंग के कपड़ों में नजर आए। उन्हें इस अंदाज में देखकर अभिषेक नायर ने मजाक करते हुए पूछा कि क्या यह उनकी अगली आईपीएल टीम का संकेत है। पीला रंग होने के कारण इशारा चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ था। इसके बाद नायर ने मजाक को आगे बढ़ाते हुए कहा कि पीला और गोल्ड रंग रोहित पर ज्यादा अच्छा लगता है। इस तरह उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को भी बातचीत में शामिल कर लिया। तभी वहां मौजूद दर्शकों ने श्मुंबई, मुंबईश के नारे लगाने शुरू कर दिए। दर्शकों के इस रिएक्शन पर रोहित ने सिर्फ एक शब्द कहा– श्फॉरएवरश यानी हमेशा। रोहित के इस जवाब ने मुंबई इंडियंस के प्रशंसकों को खुश कर दिया।

19 सितंबर से शुरू होगा रोहित का नया शो

रोहित शर्मा का टेलीविजन होस्ट के तौर पर फॅमिली फुल हाउस विद रोहित शर्मा में डेब्यू है। यह शो 19 सितंबर से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर प्रसारित होगा। आईपीएल को लेकर रोहित और नायर के बीच यह मजाक ऐसे समय में हुआ है जब मुंबई इंडियंस को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आईपीएल 2026 में मुंबई की टीम नौवें स्थान पर रही थी और उसके खाते में सिर्फ चार जीत आई थीं।

2038 एशियन गेम्स की मेजबानी कौन करेगा



स्पोर्ट्स डेस्क। भारत ने 2038 एशियन गेम्स की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है और वह छह इच्छुक देशों में शामिल है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया अगले साल सभी दावेदार देशों का शुरुआती मूल्यांकन करेगा। इसके बाद शॉर्टलिस्ट और दूसरे दौर के निरीक्षण होंगे। मेजबान के चयन की प्रक्रिया 2028 तक पूरी होने की उम्मीद है। भारत को 2038 एशियन गेम्स की मेजबानी हासिल करने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया (व्।) ने पुष्टि की है कि भारत समेत छह देशों ने 2038 एशियन गेम्स की मेजबानी में रुचि दिखाई है। अंतिम मेजबान का फैसला 2028 के आसपास होने की उम्मीद है। भारत ने अप्रैल में 2038 एशियन गेम्स के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा किया था। यह देश की बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी करने की व्यापक योजना का हिस्सा है। भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए भी दावेदारी कर रहा है, जबकि 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद में होने हैं।

अगले साल से शुरू होगा देशों का मूल्यांकन

2026 एशियन गेम्स की शुरुआत से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओसीए के महानिदेशक हुसैन अल–मुसल्लम ने मेजबानी प्रक्रिया की जानकारी दी। उन्होंने कहा, श्हमें भारत, फिलीपींस और चार अन्य देशों से 2038 एशियन गेम्स की मेजबानी में रुचि मिली है। यह एशियन गेम्स की लोकप्रियता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा, अभी 12 साल बाकी हैं। कार्यक्रम पहले से तय है। कार्यकारी बोर्ड ने एक मूल्यांकन समिति बनाने का फैसला किया है, जो अगले साल इन सभी दावेदार देशों का दौरा करेगी और फिर शुरुआती रिपोर्ट सौंपेगी। यानी भारत समेत सभी इच्छुक देशों का वास्तविक मूल्यांकन अगले साल से शुरू होगा।

शॉर्टलिस्ट के बाद होगा दूसरा दौरा

ओसीए पहले दौर के निरीक्षण के आधार पर दावेदार देशों की शॉर्टलिस्ट तैयार करेगा। इसके बाद 2038 एशियन गेम्स के करीब आने पर दूसरे दौर का मूल्यांकन किया जाएगा। अल–मुसल्लम ने कहा, श्शुरुआती रिपोर्ट के आधार पर हम एक शॉर्टलिस्ट बनाएंगे और फिर 2038 से नौ या दस साल पहले दोबारा दौरा करेंगे। इसके बाद मेजबान की सिफारिश करते हुए अंतिम रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इस प्रक्रिया के चलते भारत को अपनी दावेदारी के अंतिम परिणाम के लिए कम से कम 2028 तक इंतजार करना पड़ सकता है।

पृथ्वी शा की सगाई टूटी



भारतीय क्रिकेटर की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने की पुष्टि

स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पृथ्वी की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने उनसे अलग होने का एलान कर दिया है। पृथ्वी और आकृति की सगाई इस साल मार्च में हुई थी।

भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर चल रहे सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ की पेशेवर जिंदगी के साथ–साथ निजी जिंदगी भी मुश्किलों से गुजर रही है। पृथ्वी एक बार फिर से अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। पृथ्वी की मंगेतर आकृति अग्रवाल ने सोशल मीडिया के माध्यम से उनसे अलग होने की जानकारी साझा की है। आकृति ने इंस्टाग्राम के जरिए पृथ्वी शॉ से अलग होने की जानकारी दी।

आपसी सहमति से लिया फैसला

आकृति ने लिखा, भारी मन से, मैं यह बताना चाहती हूं कि मेरे मंगेतर और मैंने अपने भविष्य के लिए अलग–अलग लक्ष्यों और हालात की वजह से अलग होने का फैसला किया है। हम एक–दूसरे से जितना प्यार और परवाह करते हैं, हमने यह मान लिया है कि हमारे रास्ते साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। अपनी जिम्मेदारियों और अभी जिन हालात का हम सामना कर रहे हैं, उन्हें देखते हुए हमने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। आकृति ने आगे लिखा, मैं सच में हम दोनों के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छी शांति और खुशी की कामना करती हूं। मैं सभी से अनुरोध करती हूं कि इस मुश्किल समय में हमारी निजता का सम्मान करें और हमारे फैसले के पीछे के कारणों के बारे में अंदाजा लगाने से बचें।

दी नेक्स्ट पोस्ट

स्वामी मुद्रक एवं प्रकाशक बृजेन्द्र कुमार द्वारा फाइन ऑफसेट प्रिन्टर्स मदरसा हुसैनिया बिल्डिंग बक्सीपुर गोरखपुर से मुद्रित एवं 665 बी गंगा टोला, निकट जानकी बिल्डिंग मैटेरियल बसारतपुर पश्चिमी, गोरखपुर से प्रकाशित। पिनः– 273003

UPHIN/2023/90814

बृजेन्द्र कुमार

मो0. नं0. 7307180148,9170772370

Email- thenextpost01@gmail.com

नोटः– समाचार पत्र से सम्बन्धित सभी वाद-विवाद गोरखपुर जिला न्यायालय के अन्तर्गत मान्य होगे।

अफगानिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा का तूफान

भारत के लिए जड़ा सबसे तेज शतक, रोहित के रिकार्ड को पीछे छोड़ा



स्पोर्ट्स डेस्क। भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ 30 गेंदों पर शतक जड़ दिया है। अभिषेक ने भारत के लिए टी20 में सबसे तेज शतक लगाया है। अभिषेक और सैमसन के बीच शानदार साझेदारी हुई है। भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने अफगानिस्तान के खिलाफ तीसरे टी20 मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया। अभिषेक ने शतक लगाया। भारत ने इसके साथ ही पावरप्ले में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया। अभिषेक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए पहले 16 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और फिर 30 गेंदों पर शतक लगाया। टेस्ट खेलने वाले देशों में किसी बल्लेबाज का टी20 अंतरराष्ट्रीय में यह सबसे तेज शतक है।

पावरप्ले में ही पार किया 100 रनों का आंकड़ा

भारत को अभिषेक और संजू सैमसन ने दमदार शुरुआत दिलाई। दोनों बल्लेबाजों ने पहले ही ओवर से धुआंधार बल्लेबाजी की। सबसे पहले अभिषेक ने गेंदबाजों को निशाने पर लेना शुरू किया और इसके बाद सैमसन ने भी हाथ खोले। इन दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में ही 100 रनों का आंकड़ा पार करा दिया। भारत का पावरप्ले में यह अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। भारतीय टीम इससे पहले कभी पावरप्ले में 100 रन नहीं बना सकी थी।

रोहित शर्मा को पीछे छोड़ा

अभिषेक का यह शतक भारत के लिए टी20 में किसी बल्लेबाज का सबसे तेज सैकड़ा है। इससे पहले ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम था जिन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ इंदौर में खेले गए मैच में 35 गेंदों पर शतक लगाया था। किसी टेस्ट नेशन देश के बल्लेबाज का भी यह सबसे तेज शतक है। हालांकि, टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड एस्टोनिया के साहिल चौहान के नाम है। साहिल ने 2024 में साइप्रस के खिलाफ 27 गेंदों पर शतक लगाया था।